राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 15, अंक 87 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये दुर्ग, शुक्रवार 06 फरवरी 2026 www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

नक्सल अभियान में बड़ी कामयाबी, 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुल 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण एनकाउंटर, बीजापुर में नक्सली ढेर; ऑपरेशन जारी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टी की। जिले के दक्षिणी हिस्से के जंगल में सुबह 7:30 बजे यह फायरिंग शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम एंटी-नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। एक अधिकारी के अनुसार फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक मुठभेड़ स्थल से एक नक्सली का शव और एक एके-47 राइफल बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी ऑपरेशन समाप्त होने के बाद साझा की जाएगी। इस कार्रवाई के साथ, इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में कम से कम 23 माओवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले, तीन जनवरी को बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ों में 14 माओवादी ढेर किए गए थे। बस्तर क्षेत्र में सात जिले आते हैं, जिनमें बीजापुर भी शामिल है। पिछले साल, छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ों में कुल 285 माओवादी मारे गए थे। केंद्र ने इस साल 31 मार्च तक देश से लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने की समयसीमा निर्धारित की है।

उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी छिपे

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में मंगलवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गोली लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि दो आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर के अंतर्गत ष्टद्धस्त्र डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद बसंतगढ़ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रामनगर के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वह अपने साथी के साथ गुफा के भीतर घुस गया। सूत्रों के अनुसार, गुफा में दो संभावित निकास मार्ग हैं, जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर सील कर दिया है। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए।

मोहब्बत की दुकान वाले 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहे

राज्यसभा में बोले पीएम मोदी-रोज दो किलो गाली खाता हूं..

नई दिल्ली। एजेंसी

संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया। विपक्ष की ओर से जोरदार नारेबाजी के बीच उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। देश आज तेज प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरी एक प्रार्थना है। आदरणीय खरगे जी की उम्र को देखते हुए, अगर वे बैठकर भी नारे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पीछे कई सारे युवा नेता हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग, गरीब, गांव, किसान, महिलाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। राष्ट्रपति ने भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति भी भरोसा जताया है। यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, देश का हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़कर देखना है। हम आगे ही आगे देखना है और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत के भाग्य के लिए अनेक संयोग एक साथ हमें नसीब हुए हैं। ये

अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है। सबसे बड़ी बात है कि विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है, जिन्हें हम बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है, जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वैसे ही देश हमारा युवा होता जा रहा है। युवा आबादी वाला देश बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरी तरफमैं देख रहा हूं जिस प्रकार विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विश्व भारत के प्रतिभा (टैलेंट) का अहमियत समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही अहम टैलेंट पूल है। युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने, संकल्प और सामर्थ्य है। यानी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, भारत उनका समाधान देने, आशा की किरण देने वाला देश बना हुआ है। हम समाधान दे रहे हैं। आज अहम अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर काफी ऊंची है। ऊंची विकास दर और कम महंगाई एक अनोखी उपलब्धि है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए, तब देश छठी नंबर की अर्थव्यवस्था था। आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में एक आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। कोविड के बाद जो स्थितियां पैदा हुईं, दुनिया आज भी उनसे संभल नहीं पा रही है।

पीएमकी स्पीच के बिना पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव 2004 के बाद पहली बार

नई दिल्ली। बजट सत्र के सातवें दिन लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। खास बात यह रही कि 2004 के बाद यह पहला मौका है जब यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना ही पास हुआ। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष के विरोध के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल नहीं पाए थे। गुरुवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्पीकर को बार-बार सदन स्थगित करना पड़ा। पहली बार महज 65 सेकंड में, दूसरी बार 5 मिनट और तीसरी बार केवल 2 मिनट में कार्यवाही रोकनी पड़ी। दोपहर 3 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ।

असम सीएम और मोदी पर बरसे ओवैसी

चांद पर घर और मिया को एक रुपया नहीं?

नई दिल्ली। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 'मियां' समुदाय पर दिए गए बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय का अपमान बताते हुए पीएम मोदी के 'विकसित भारत' और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 'मियां' समुदाय को लेकर दी जा रही तीखी बयानबाजी ने देश की सियासत को गरमा दिया है।

सीएम सरमा ने हाल ही में कहा था कि इस समुदाय के लोगों को असम में रहने का अधिकार नहीं है और न ही ये यहां रिक्शा चला सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि वे शांति चाहते हैं तो यहां से चले जाएं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के दौरान भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुईं।

करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन गिरफ्तार.....

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को करोड़ों की जालसाजी और अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दर्ज कराई गई 2 एफआईआर के आधार पर की गई है।पुलिस के मुताबिक दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। धमाके के बाद से ही अल फला यूनिवर्सिटी के

संचालन से जुड़ी कई अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की जांच को शुरू किया गया था। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर ही क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

यूपी में अब कातिल मांझे पर मर्डर केस

योगी का फैसला-चाइनीज मांझे से मौत को माना जाएगा हत्या....

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे के कारण हो रहे जानलेवा हादसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे 'हत्या' की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया है। लखनऊ में एक युवक की गर्दन कटने से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में छापेमारी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 फरवरी को हुई एक हृदय विदारक घटना ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। दुबग्गा की सीते विहार कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद शोएब, जो

एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अपनी स्कूटी से मार्केट जा रहे थे। जब वे हैदरगंज चौराहे से तालकटोरा मिल एरिया वाले फ्लाईओवर पर चढ़े, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मांझे के खिंचाव के कारण शोएब की गर्दन काफी गहरी कट गई और वे लहूलुहान होकर स्कूटी से नीचे गिर गए। उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शोएब अपने परिवार के इकलौते सहारा थे; उनके पीछे उनकी पत्नी, दो छोटी बेटियां और बूढ़ी मां रह गई हैं। इस हादसे ने एक बार फिर प्रतिबंधित मांझे की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जाहिर की है।, उन्होंने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अब सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या माना जाएगा।

भारत ने कृषि और दुग्ध क्षेत्रों की रक्षा की, ट्रेड डील पर लोकसभा में बोले पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत ने अपने कृषि और दुग्ध क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षित रखने में सफलता हासिल की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ...पिछले साल दोनों पक्षों के बातचीत करने वालों ने अलग-अलग लेवल पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों के ज़रूरी हितों को ध्यान में रखते हुए, यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपने-अपने ज़रूरी।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

कर्मचारियों को 11 साल का 25 प्रतिशत डीए देने का आदेश......

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बकाया डीए का 25 प्रतिशत हिस्सा 6 मार्च तक कर्मचारियों को दिया जाए। साथ ही, शेष राशि किस्तों में कैसे चुकाई जाएगी, यह तय करने के

लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस समिति में जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान, जस्टिस गौतम विधूडी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (ष्टत्र) का एक अधिकारी शामिल होगा। कमेटी यह तय करेगी कि बकाया ष्ठ का भुगतान किस तरीके से किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 16 मई तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई भी 16 मई को तय की गई है। इस फैसले से करीब 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार के अनुसार, बकाया डीएके भुगतान में लगभग 43 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना उनका अधिकार है। ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया था।

भीषण धमाके से दहला मेघालय!

कोयला खदान में हुआ भयंकर विस्फोट,10 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली/ एजेंसी

पूर्वोत्तर भारत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां मेघालय की एक कोयला खदान में भयंकर विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इस भयावह हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह धमाका मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुआ है। बताया जा रहा है कि मौके पर राहत एवं बचाव दल पहुंच चुका है। इस धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के लिए एक टीम भेजी गई है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो

पाई है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मृतक असम के रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा गया। प्रशासन ने धमाके के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में गैस लीक या किसी टेक्निकल खराबी को संभावित कारण बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घटनास्थल से मिली रिपोर्टों के अनुसार, जिस पहाड़ी पर अवैध खनन हो रहा था वह धमाके के बाद आंशिक रूप से ढह गई। इसमें और भी मजदूरों के फंसे होने की आशंका है इस घटना ने एक बार फिर मेघालय में अवैध माइनिंग ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खदान के अंदर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया गया था? इन सभी बातों की अब जांच की जाएगी, लेकिन 10 बेगुनाह लोगों की मौत यह साबित करती है कि मजदूरों की जान की कीमत कोयले से कम समझी जा रही है।

रायगढ़ मंगल कार्बन प्लांट में ब्लास्ट: टायर गलाने के दौरान हुआ विस्फोट,मासूम समेत आठ मजदूर झुलसे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गुरुवार सुबह मंगल कॉर्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक मासूम सहित आठ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बानीपाथर गांव में स्थित मंगल कार्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस दौरान वहां काम कर रहे डेढ़ साल की मासूम भूमि खडिया, इंद्रजीत, प्रिया सारथी, साहेबराम खडिया, कौशल कुमार, शिव खडिया, उदासीन खडिया, इंद्रवद सहित कई अन्य मजदूर झुलस गए। जानकारी के अनुसार मंगल कार्बन प्लांट में काम कर रहे मजदूरों द्वारा टायर गलाने वाले ब्लाडर को खोलते वक्त प्रेशर से दो नट अपने आप खुलते ही ब्लास्ट हो गया। और फिर यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही, जिसके बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के सभी सभी घायलों को एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल कुमार जगत ने बताया कि खरसिया के चोढा के पास स्थित फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगने की घटना में कई लोग झुलस गए।

संक्षिप्त समाचार

रामायण पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें राम जी के आदर्शों पर भी चलना होगा : जगजीत सिंह भाटिया

छुरिया। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों राजाटोला, खुर्शीटिकुल, तुमड़ीलेवा, चिखली, सोनसायटोला व मांगाटोला में समस्त ग्रामवासियों के तत्वधान में दो दिवसीय मानस गान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके बतौर समापन समारोह के मुख्य अतिथि जगजीत सिंह भाटिया (उपाध्यक्ष, जिला भाजपा, राजनांदगांव), अध्यक्षता पुनऊ राम फुलकौर (अध्यक्ष जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी), संजय सिन्हा (अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया), गोवर्धन नेताम (पूर्व मंत्री छग), रविंद्र वैष्णव (पूर्व महामंत्री जिला राजनांदगांव), विशेष अतिथि हीरेन्द्र साहू (जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा राजनांदगांव), श्रीमती भारती देवांगन जनपद सदस्य, श्रीमती नेहा मंडलोई (सरपंच सोमाझिटीया), श्रीमती तिलकी अशोक मानकर जी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भाटिया ने कहा कि रामायण पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, राम जी के आदर्शों पर भी हमें चलना होगा, जैसे-रामायण में गुरु के प्रति समर्पण, भाई-भाई का आपसी प्रेम, सास-बहू का तालमेल और मित्रता का आदर्श परिलक्षित होता है, इसी प्रकार हमारे घर परिवार और समाज में ही इन बातों को आचरण में लाने की आवश्यकता है। रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती व सदा शुभ आचरण करना सिखाती है, यदि हम अपने जीवन में रामायण के किसी एक संदेश को भी अपनाते हैं, तो इससे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसका मुझे विश्वास है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गयादास साहू उपाध्यक्ष अंबागढ़ चौकी, कुंदन साहू, श्रीमती गुलाब बाई उपसरपंच, गोपाल साहू पूर्व मंडल अध्यक्ष कुमरदा, मंतूराम वामन, यमन साहू, दुष्यंत साहू, मोरध्वज देवांगन, दुर्गा प्रसाद, हुकुम साहू, चंदन दखने ग्राम अध्यक्ष, दयाल चंद्रवंशी, मधुराम साहू, श्रीमती तीजन बाई मानिकपुरी, गुलाब दास साहू, मोहन भारद्वाज, आनंद साहू, रिकू राम साहू, प्रहलाद साहू, रविंद्र कुमार साहू, लिलेश्वर साहू, अश्वनी साहू एवं समस्त ग्रामों के ग्रामवासीगण व मानस समिति के सदस्य उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत पंहडोर को टी बी मुक्त बनाने प्रयास जारी

पाटन। ग्राम पंचायत पंहडोर को टी बी मुक्त बनाने प्रयास जारी हैं इस वर्ष एक भी टी बी(क्षय रोगी) नहीं मिल पाया है पुराने मरीज ने अपनी दवा पूर्ण कर लिया है बी ई टी ओ व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सैय्यद असलम ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज दानी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ भुवनेश्वर कठौतिया के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग टी बी मुक्त जिला बनाने अभियान छेड़ा है इसके लिए सामुहिक प्रयासों की आवश्यकता है ग्राम पंचायत पंहडोर में सरपंच पंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला, आयुष के कर्मचारियों की संगोष्ठी आयोजित किया गया है टी बी के प्रमुख लक्षण को प्रत्येक को बताकर ऐसे लोगों की जांच कराने और पूरी दवा खिलाने सहयोग करने कहा गया बुखार आना वज़न कम होना भूख नहीं लगना लगातार खांसी और बलगम में खून आना टी बी के प्रमुख लक्षण हैं सरपंच श्रीमती मढरिया ने लोगों से कहा कि नशा,बी डी, सिगरेट-शराब जैसे पदार्थों का सेवन फेफड़ों को खराब करता है टी बी रोग संक्रमण रोग है जो फेफड़ों को प्रमुखता प्रभावित करता है इसलिए नशा पानी से मुक्त करके ऐसे रोगो से बचाव निदान हो सकता है कार्यक्रम में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका श्रीमती वेगु गवेल स्वास्थ्य संयोजक जितेन्द्र पटेल ने टी बी रोगियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मिलने वाली सुविधाएं की जानकारी दी कार्यक्रम में सरपंच पंच, मितानिन , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुष कर्मचारी जन प्रतिनिधि ओर ग्रामीण उपस्थित थे

निधन : सराफा व्यवसायी ललित चंद्र सांगाणी

दुर्ग। पद्मनाभपुर निवासी एवं सराफ व्यवसायी ललित चंद्र सांगाणी 79 वर्ष का गुरुवार की सुबह आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार हरनाबांधा मुक्तिधाम में किया गया। वे ताराचंद सांगाणी के बड़े भाई एवं प्रणेश सांगाणी के पिताजी थे। स्व. ललित चंद्र सांगाणी कांतिलाल ज्वेलर्स के संचालक एवं गुजराती समाज दुर्ग के सक्रिय सदस्य थे। उनके अंतिम यात्रा में शहर के गणमान्य नागरिक, गुजराती समाज के सदस्य एवं सराफ व्यवसाई शामिल हुए। स्व. ललित चंद्र सांगाणी के निधन पर दुर्ग सराफ व्यवसायियों ने अपनी दुकाने बंद रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

यातायात अव्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। नगर में लगातार बिगड़ती जा रही यातायात व्यवस्था को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने गंभीर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से मुलाकात कर नगर की यातायात समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि नगर में बेरोकटोक भारी वाहनों की आवाजाही, बसों के मनमाने स्टापेज, चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति और बेतरतीब पार्किंग के चलते आम नागरिकों को भारी दबाव और जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चार पहिया और तीन पहिया वाहनों की आवाजाही सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, जिससे दैनिक जीवन और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। इसके साथ ही नेशनल हाइवे में बंद पड़ी हाईमास्ट लाइटों के कारण रात के समय दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है।

इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार की व्यापक गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर अमल करना होगा। केवल एक विभाग के प्रयास से स्थिति नहीं सुधर सकती।

मुदलियार ने स्पष्ट कहा कि यातायात सुधार के नाम पर आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशान करना स्वीकार्य नहीं है। व्यवस्था इस तरह बनाई जाए कि सर्विस लेन और प्रमुख चौक-चौराहों पर आवागमन सुगम हो, भारी वाहनों के दबाव को नियंत्रित किया जाए और बसों को तय स्टापेज पर ही रोका जाए।

जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राजनांदगांव की जनता को जाम, अव्यवस्थित ट्रैफिक और अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके। मुदलियार ने कहा कि जनता से जुड़ी इन समस्याओं पर अगर 15 दिनों में सुधार लागू नहीं हुए तो पुलिस अधिक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान रुपेश दुबे, कमलजीत सिंह पिंटू, सूर्यकांत जैन, एनी माखिजा, अशोक पंजवानी, विनय झा, राजेश चंपू गुप्ता, मनीष गौतम, डॉ अरुण देवांगन, मोहनीश धनकर, शुभम पांडे, मोहम्मद इब्राहिम, राजिक सोलंकी, नितिन बत्रा, कुलदीप कुरंजेकर, आफ्ताब अहमद, अभिमन्यु मिश्रा, संदीप सोनी, जय जयसवाल, खूबचंद यादव, विष्णु सिन्हा, कादिर कुरैशी, वीरेंद्र चंद्राकर, राकेश चंद्राकर, गजेंद्र सिंह राजपूत, देवेश वैष्णव, लक्की चंद्राकर, आशीष साहू, राजा यादव, नरेश साहू, चंपा चंद्राकर, चेतन चंद्राकर, नीलेश ठावरे, शैलेष साहू, गोलू नायक, आशीष साहू, शेखर मालेकर, नीशू गुप्ता, बाबा राठौर, कृष्णा भारती, नरेन्द्र भारती, चेतन चंद्राकर, हेमचंद यादव, तेजराम साहू, नीतेश मारकंडे, देवचंद डिंडे, कमलेश साहू, रिषभ निर्मलकर, चुम्मन निषाद, निलेश ठावरे, शैलेश ठावरे, राजा यादव, सीताराम निषाद, मानसिंग साहू, शेख आशिफ चैतराम साहू सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

सांकरा पुकिस ने गांजा तस्करी मामले में परिवहनकर्ता वाहन स्वामी सहित मामले के मुख्य विक्रेता को किया गिरफ्तार

पिथौरा(समय दर्शन)। गांजा तस्करी करने, कार्यरत पुलिसकर्मी को अपने वाहन से कुचलने का प्रयास करने एवं पुलिस वाहन को ठोकर मारने के कारण वाहन में आग लग जाने व वाहन क्षतिग्रस्त मामले में महासमुंद पुलिस ने अहम सफलता हासिल करते हुवे दो आरोपियो को गिरफ्तार किया है। दोनो आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले है। जिसमें राकेश चौकसे उम्र 32 वर्ष परिवहनकर्ता एवं मोनू राय उम्र 34 वर्ष फारवर्ड लिंक एवं वाहन स्वामी है। ये आरोपी एक वर्ष में 6 बार में 350 किलो गांजा तस्करी कर चुके है। दरअसल 22-23 जनवरी को सांकरा पुलिस को सूचना मिली थी । एक मारुति की ईको कार क्रमांक-स्क्क 05 श्व- 8685 में गांजा जाने वाला है। पुलिस सूचना के आधार ईको कार को रोकने का प्रयास की । ईको कार चालक वाहन रोकने के बजाय तेज गति से पुलिस स्टाफ को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पीछा किया तो ईको कार चालक ने पुलिस के वाहन को तीन बार ठोकर मारी, जिससे पुलिस का वाहन पूरी तरह जल गयी। उसके बाद आरोपी ईको कार वही छोड़कर फरार हो गये । पुलिस को कार से 19 लाख 84 हजार का 39.680 किलो गांजा मिला ,जो उड़ीसा से गांजा लेकर मध्यप्रदेश जा रहे थे । मामले में पुलिस ने 14 दिन की जांच के बाद दो आरोपियो को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लाई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनो आरोपियो पर बी एन एस की धारा 324(5), 132, 109 एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। गौरतलब है कि इसी मामले में पुलिस कि अभी-अभी एक सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मामले के मुख्य गांजा विक्रेता बालाकृष्ण को भी बलांगीर से गिरफ्तार कर लिया है।

गांधीडीह, लोरमी के आसपास की छात्राओं को मिला सुसज्जित छात्रावास

एक ही परिसर में सर्वसुविधायुक्त 04 कन्या छात्रावास से बालिका शिक्षा की राह हुई आसान

मुंगेली(समय दर्शन) लोरमी के गांधीडीह क्षेत्र में कन्या शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के अंतर्गत 04 कन्या छात्रावासों का एक ही परिसर में निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में इन छात्रावासों का विधिवत शुभारंभ 01 जनवरी 2026 से किया जा चुका है, जिसके पश्चात छात्रावास में कक्षा पहली से लेकर कालेज तक की छात्राएं आवासरत हैं। यह पहल न केवल छात्राओं की आवासीय समस्या का समाधान है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस पहल भी है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त शिवकुमार बांधे ने बताया कि पूर्व में छात्राओं को किराए के भवनों में रहना पड़ता था, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी व जगह का अभाव होने के कारण स्वीकृत सीट के अनुरूप छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पाता था। अब स्वयं के भवन में संचालन होने से पर्याप्त स्थान, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, अध्ययन कक्ष एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं संतोषजनक रूप से उपलब्ध हो पाएगी। इसका सीधा प्रभाव छात्राओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शासन की पहल पर नव-निर्मित कन्या छात्रावासों में छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन छात्रावासों में सुरक्षित एवं स्वच्छ आवास, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय, अध्ययन हेतु शांत एवं अनुकूल वातावरण के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर प्रबंध जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे छात्राएं अब निश्चिंत होकर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह परियोजना केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सुरक्षित छात्रावास की उपलब्धता से अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ा है, जिससे अधिक संख्या में बालिकाएं शिक्षा से जुड़ सकेंगी।

हिंदू जागरण मंच ने वाईडनर स्कूल परिसर में संचालित चर्च को बंद कराने सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। हिंदू जागरण मंच, राजनांदगांव द्वारा वाईडनर स्कूल परिसर में संचालित चर्च को बंद कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मंच पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लालबाग स्थित राजगामी संपदा की लगभग 5 एकड़ भूमि शासन द्वारा विद्यालय संचालन के उद्देश्य से आबंटित की गई थी, किंतु वहां शर्तों के विपरीत भव्य चर्च का निर्माण कर उसका उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

ज्ञापन में हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि उक्त परिसर में हिंदू समाज के विरुद्ध मतांतरण एवं धर्मांतरण जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो भूमि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मंच का कहना है कि यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला भी है। मंच ने प्रशासन से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराई जाए, यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि किन शर्तों पर दी गई थी और क्या उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यदि जांच में उल्लंघन पाया जाता है तो अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए, चर्च को बंद कराया जाए तथा नियमानुसार दी गई संपत्ति को वापस लेने की कार्रवाई की जाए।

हिंदू जागरण मंच ने यह भी आग्रह किया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन से मामले में शीघ्र निर्णय लेकर जनभावनाओं का सम्मान करने की मांग की गई। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सुशील लड्ढा, सविता बोस, प्रवीण शर्मा, प्रभात गुप्ता, राजा जुगल गुप्ता, हरीश भानुशाली, महेंद्र जंघेल, कुबेर साहू, गोविंद साहू, रिंकू तिवारी, आशीष तिवारी, मुकेश सोनी, रोहित यादव, कमलेश साहू, राज सोनकर, मनोज गोलछा, मौसमी शर्मा, राजबहादुर सिंह, दिनेश झूलन, हिटू व्यास, हेमलाल ढीमर, टिंकू सोनी, राकेश, कालू सेन एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने दमदार नए डियो 125 X- एडिशन के साथ क्लीन और एलिगेंट शाइन 125 लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया

नई दिल्ली: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आज दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए डियो 125 X-एडिशन, जिसकी कीमत 87,733 है, और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, जिसकी कीमत 86,211 है (दिल्ली एक्स-शोरूम)। आज के बदलते राइडर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए ये दोनों स्पेशल एडिशन एक रिफ्रेश्ड आइडेंटिटी, आकर्षक नए ग्राफिक्स और प्रीमियम डिज़ाइन एन्हांसमेंट्स के साथ पेश किए गए हैं, जो तेज़ी से बढ़ते भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में इनकी अपील को और बढ़ाते हैं। नए स्पेशल एडिशन पेश करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ श्री त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा, होंडा में हम लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का प्रयास करते हैं जो भारत के न्यू-एज राइडर्स की आकांक्षाओं से जुड़ें। बिल्कुल नया डियो 125 X-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, स्टाइल की नई अभिव्यक्तियां पेश करने के साथ-साथ उस भरोसे और विश्वसनीयता को भी दर्शाते हैं, जिसकी उम्मीद ग्राहक होंडा से करते हैं। ये लिमिटेड एडिशन एक्सप्रेसिव डिज़ाइन को होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं, ताकि हर राइड आत्मविश्वास भरी और सहज महसूस हो। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, श्री योगेश माथुर ने कहा, डियो 125 X-एडिशन होंडा की अपनी जेन ॅ डिज़ाइन टीम द्वारा तैयार की गई बोल्ड और यूथफुल एनर्जी के साथ आता है, जो आज के युवा राइडर्स की व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। वहीं, शाइन 125 लिमिटेड एडिशन एक क्लीन और टाइमलेस डिज़ाइन अप्रोच अपनाता है, जो मोटरसाइकिल के स्लीक स्कल्प्चर्ड फॉर्म और रिफाइंड लुक को उभारता है। इन नए एडिशन्स के साथ हमारा लक्ष्य राइडर्स को स्टाइल, कम्फर्ट और रोज़मर्रा की भरोसेमंद परफॉर्मेंस का संतुलन देना है, ताकि वे सड़क पर आत्मविश्वास के साथ खुद को अभिव्यक्त कर सकें। दोनों मॉडल होंडा के सोच- समझकर किए गए डिज़ाइन और सभी के लिए सुरक्षित व सहज राइडिंग अनुभव पर फोकस को बरकरार रखते हैं।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत पुणे में प्रशिक्षित हुए छत्तीसगढ़ के चयनित शिक्षक

बसना(समय दर्शन)। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (ढ्ढस्श्वक्र), पुणे में 28 से 30 जनवरी तक आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य के 100 चयनित शिक्षकों ने सहभागिता की। इस कार्यशाला में महासमुन्द जिले से भी चयनित शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

विषय सूची : राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में वैज्ञानिक सोच और नवाचार से बच्चों को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।

महासमुन्द जिले से इन शिक्षकों ने किया जिले का प्रतिनिधित्व।

विज्ञान को अनुभव से जोड़ने का मिला अवसर।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में वैज्ञानिक सोच और नवाचार से बच्चों को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।

कार्यशाला का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें आयुक्त श्रीमती किरण कौशल, उपसंचालक डी. के. सारस्वत, सह संचालक श्रीमती मंजू लता साहू, एपीसी राजेश सोनकर के मार्गदर्शन एवं एपीसी बसंत कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह शैक्षणिक दल पुणे पहुँचा।

महासमुन्द जिले से इन शिक्षकों ने किया जिले का प्रतिनिधित्व।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत महासमुन्द जिले से चयनित शिक्षकों में —

मधु कुमार साहू, शा. पूर्व माध्यमिक शाला देवरी, विकासखंड बागबाहरा। श्रीमती उत्तरा कुमार चौधरी, विकासखंड बसना। श्रीमती खेमलता प्रधान, पिथौरा।

श्रीमती लक्ष्मी नायक, सरायपाली। शामिल रहीं, जिन्होंने कार्यशाला के दौरान उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए जिले का गौरव बढ़ाया।

विज्ञान को अनुभव से जोड़ने का मिला अवसर।

इस अभियान के अंतर्गत शिक्षकों ने साइंस सेंटर का अवलोकन, कल्पक घर में सरल वैज्ञानिक प्रयोग, तारामंडल की सैर, खगोलीय पिंडों का प्रत्यक्ष ज्ञान, विभिन्न अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण तथा वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। यह अनुभव शिक्षकों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि रोमांचक और प्रेरणादायी भी रहा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण।

कार्यशाला में नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए —

गतिविधि आधारित शिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ढ्ढष्टञ्ज) का प्रभावी उपयोग-बच्चों में वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास,कम लागत में शिक्षण-अधिगम सामग्री (ञ्जरुरू) निर्माण,तथा शिक्षा में नवाचार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान प्रवृत्ति विकसित करने हेतु विशेष सत्र आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यशाला प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित की गई, जो अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई।कार्यशाला से लौटे शिक्षकों ने कहा कि यह प्रशिक्षण कक्षा-कक्ष में विज्ञान शिक्षण को और अधिक रोचक, व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जशपुर को मिली पर्यटन विकास की बड़ी सौगात

ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा मयाली - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उप-योजना सीबीडीडी के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना के तहत मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत (विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग) तथा बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

यह परियोजना क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाएगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जशपुर जिले को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में नई पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मयाली-बगीचा विकास परियोजना जशपुर जिले के पर्यटन विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। आज मयाली के विकास की मजबूत नींव रखी गई है। मयाली अब पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में यह एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मयाली की पहचान सदियों से मधेश्वर महादेव से जुड़ी रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस विकास परियोजना के माध्यम से मधेश्वर पर्वत के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत मयाली डेम के समीप पर्यटक रिसोर्ट एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मयाली को एक समग्र इको-टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां के जंगल, झरने, पहाड़ और

समृद्ध आदिवासी संस्कृति को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटन से होने वाली आय का सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। श्री साय ने कहा इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा होम-स्टे नीति लागू की गई है, जिससे ग्रामीण परिवार पर्यटन गतिविधियों से सीधे जुड़कर आय अर्जित कर सकेंगे और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में टूर गाइड, होटल सेवा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हस्तशिल्प एवं डिजिटल बुकिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन बल्कि जशपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

मयाली क्षेत्र को प्राकृतिक, धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन के समग्र गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 5 पर्यटक कॉटेज, कॉन्फ्रेंस एवं कन्वेंशन हॉल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, भव्य प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, आधुनिक टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं से पर्यटकों के ठहराव एवं विभिन्न आयोजनों की बेहतर व्यवस्था होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार्मिक पर्यटन को सशक्त करने के लिए शिव मंदिर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का विकास किया जाएगा। वहीं बगीचा स्थित कैलाश गुफा परिसर में प्रवेश द्वार, पिकनिक स्पॉट, रेस्टिंग शेड, घाट विकास, पाथवे तथा सीढ़ियों एवं रेलिंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक अनुभव मिलेगा।

पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स से युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अलग अंदाज़ में नजर आए और उन्होंने 10 रूपए का टिकट कटाकर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेल गतिविधियों का आनंद लिया और कई नए एडवेंचर स्पोर्ट्स की औपचारिक शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने प्रवेश शुल्क अदा कर नेचर कैंप में प्रवेश करते हुए आम नागरिकों को नियमों के पालन और समानता का एक सशक्त संदेश दिया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, विधायक श्रीमती गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान नेचर कैंप में विकसित अधोसंरचनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रकृति-आधारित पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करती हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने मयाली नेचर कैंप में संचालित स्पोर्ट्स मोटर बाइक (एटीवी) को स्वयं चलाकर साहसिक पर्यटन का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने बंदूक से सटीक निशाना साधते हुए बैलून शूटिंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आर्चरी शूटिंग में तीर चलाकर निशाना साधा और इस खेल की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने माउंटेन साइक्लिंग का शुभारंभ करते हुए स्वयं साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। नेचर कैंप में वॉल क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस दौरान वॉल क्लाइंबर तेज सिंह एवं तेजल भगत ने मुख्यमंत्री के समक्ष वॉल क्लाइंबिंग कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय बॉक्स क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हुए नजर आए और स्टेट ड्राइव व ऑफ साइड पर आकर्षक शॉट लगाए। मुख्यमंत्री ने मयाली नेचर कैंप स्थित कैक्टस गार्डन का अवलोकन किया, जहां विभिन्न प्रजातियों के कैक्टस लगाए गए हैं वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार ने कैक्टस के औषधीय महत्व की जानकारी दी।

नारी शक्ति की उड़ानः बिहान योजना से आत्मनिर्भर बनी सुखमंती बैगा

रायपुर। मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला के ग्राम पंचायत रामगढ़ की निवासी श्रीमती सुखमंती बैगा आज नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले जहां परिवार की आय सीमित थी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं आज वे अपने परिश्रम और योजना से मिले सहयोग के बल पर सम्मानजनक आजीविका अर्जित कर रही हैं।

ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) चला रही है द्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की क्षमता का विकास किया गया द्य महिलाएं सशक्त बनी और आज नेतृत्व कर रही हैंद्य इन

महिलाओं की सफलता के पीछे बिहान योजना का बड़ा योगदान हैं द्य क्योंकि इसी योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं में इतनी साहस आयी है सुखमंती बैगा चंगमाता स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। दिसंबर 2020 में बैंक लिंकेज के माध्यम से उन्होंने 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने अपने गांव में एक छोटी किराना दुकान शुरू की। शुरुआती दिनों में सीमित संसाधन और अनुभव की कमी जैसी चुनौतियां सामने आईं, लेकिन बिहान योजना के प्रशिक्षण, समूह की सामूहिक शक्ति और अपने आत्मविश्वास से उन्होंने धीरे-धीरे व्यवसाय को मजबूत किया।

आज उनकी किराना दुकान से उन्हें प्रतिमाह लगभग 4 से 7 हजार रुपये तक की नियमित आय हो रही है। इस आय से वे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सुखमंती बैगा अब अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी यह सफलता कहानी साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल बन सकती हैं।

महतारी वंदन योजना से श्रीमती सुलेश्वरी यादव को मिली आत्मनिर्भरता की नई राह

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना ने जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय निवासी श्रीमती सुलेश्वरी यादव के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई राह दिखाई है।

सीमित आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच जीवनयापन कर रहीं श्रीमती सुलेश्वरी यादव के लिए तीन बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च और भविष्य की जरूरतें बड़ी चुनौती थीं। घरेलू कार्यों के साथ-साथ सिलाई कार्य कर वे परिवार की आय में सहयोग करती थीं, किंतु संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्राप्त होने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि उनके लिए आर्थिक संबल बनी। उन्होंने इस राशि से नियमित बचत प्रारंभ की तथा बच्चों

की पढ़ाई, स्कूल फीस, किताब-कॉपी एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की। हाल ही में योजना की 24वीं किश्त के रूप में प्राप्त राशि से उनके परिवार को अतिरिक्त राहत मिली है।

श्रीमती सुलेश्वरी यादव का कहना है कि इस योजना से उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की एक प्रभावी पहल है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है।

upGrad ने रायपुर में लॉन्च किया अपना नया लर्निंग सपोर्ट सेंटर

रायपुर में upGrad का नया सेंटर, 4 6 महीने के हाई-इम्पैक्ट कोर्स ऑफर

स्किलिंग की प्रमुख कंपनी upGrad अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) के साथ रायपुर में आई है। स्थानीय युवाओं और शुरुआती करियर वाले प्रोफेशनल्स को सशक्त बनाने के लिए जॉब-फोकस्ड, शॉर्ट-फॉर्मेट स्किलिंग प्रोग्राम लेकर आई है।

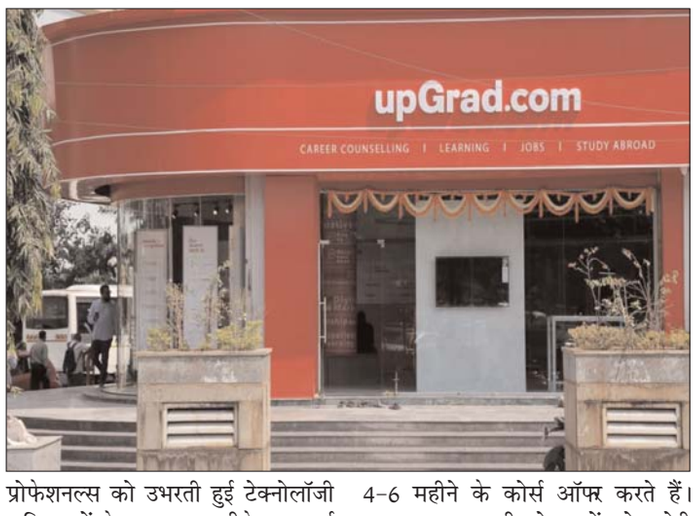

रायपुरः ग्लोबल स्किलिंग प्रमुख upGrad ने रायपुर में अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका मकसद लोकल युथ और शुरुआती करियर वाले प्रोफेशनल्स को उभरती हुई टेक्नोलॉजी भूमिकाओं के अनुरूप एप्लीकेशन-फर्स्ट स्किल्स से लैस करना है।

जयनगर, मराठाहल्ली और HSR लेआउट में हाई-इम्पैक्ट लर्निंग पॉड्स के रूप में डिज़ाइन किए गए, ये सेंटर डेटा साइंस, AI/ML और फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे हाई-डिमांड डोमेन में 4-6 महीने के कोर्स ऑफर करते हैं। इसका मकसद सीखने वालों को थ्योरी से आगे बढ़कर भारत की टेक्नोलॉजी, सेवाओं और डिजिटल इकॉनमी में हाई-ग्रोथ भूमिकाओं के लिए जॉब-रेडी बनाना है, जो अब रणनीतिक रूप से नॉन-मेट्रो शहरों में भी फैल रही है।

यह पहल upGrad के 'अपस्किल इंडिया' मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारत के बढ़ते वर्कफोर्स के लिए इंडस्ट्री से संबंधित स्किलिंग को सुलभ, किफायती और परिणाम-उन्मुख बनाया गया है — खासकर उन लोगों के लिए जो करियर में तेजी लाने के लिए तुरंत अपस्किलिंग चाहते हैं।

upGrad पहले ही बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद और मंगलुरु में 12 से ज़्यादा ऑपरेशनल सेंटर लॉन्च कर चुका है और अब यह ब्रांड रणनीतिक रूप से प्रमुख नॉन-मेट्रो हब में विस्तार कर रहा है। नए सेंटर इस राष्ट्रव्यापी विस्तार का एक रणनीतिक हिस्सा हैं, जो upGrad के व्यापक फिज़ीटल रोडमैप के साथ एक मजबूत स्थानीय स्किलिंग पुश को जोड़ते हैं।

विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, upGrad के COO – ऑफ़लाइन, मनीष कालरा ने कहा,

हर साल लाखों ग्रेजुएट वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। भारत आकांक्षा और अवसर के मुहाने पर खड़ा है, और फिर भी नियोक्ताओं की अपेक्षाओं और पारंपरिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के बीच एक बड़ा अंतर है। यहीं पर हम अपने ऑफ़लाइन स्पेस के साथ एक मजबूत इंडस्ट्री डिफरेंशिएटर बनाना चाहते हैं — ये कोचिंग सेंटर नहीं हैं, बल्कि सीखने का मतलब है सीखने वालों को जॉब-रेडी बनाना।

उन्होंने आगे कहा, रायपुर जैसे शहर टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री-रेडी स्किलिंग तक पहुंचने के लिए अक्सर मेट्रो शहरों में जाना पड़ता था। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, साथियों के साथ सहयोग और मेंटरिंग को लचीले ऑनलाइन कंटेंट के साथ मिलाकर स्थानीय लर्निंग पॉड्स की पेशकश करके, हम घर के करीब परिणाम-उन्मुख सीखने को सक्षम बना रहे हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत हर साल लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करता है, फिर भी रोज़गार एक चुनौती बना हुआ है, जिसमें से केवल 45% ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती को मिली स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में शिक्षकीय संसाधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने कुल 5000 शिक्षकीय पदों पर नवीन भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

स्कूल शिक्षा विभाग के विभागीय आदेश के माध्यम से पूर्व में 4708 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रस्ताव के अनुरूप 292 सहायक शिक्षकों के नवीन पदों के सृजन की सहमति देते हुए उन पर भी भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल स्वीकृत पदों की संख्या अब 5000 हो गई है।

उक्त भर्ती की अनुमति वित्त विभाग की सहमति के आधार पर प्रदान की गई है। इस निर्णय से राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही यह निर्णय शिक्षण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

प्रदेश के 62 शालाओं को मिलेगा नया स्कूल भवन

रायपुर। राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की कुल 62 शालाओं में नवीन भवन निर्माण हेतु 7 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 30 पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए 3.55 करोड़ तथा 32 प्राथमिक शालाओं के लिए 3.67 करोड़ की राशि स्वीकृत शामिल है। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत 30 पूर्व माध्यमिक शालाओं में जिला जशपुर के विकासखण्ड मनोरा की ओरकेला, कुनकुरी की नारायणपुर एवं खण्डसा, पत्थलगांव की बरजोर एवं बालक कोतबा, कांसाबेल की चिकनीपानी एवं कोकोन्दरी के पूर्व माध्यमिक शाला नवीन भवन निर्माण शामिल है। इसी प्रकार कोण्डागांव जिले की विकासखण्ड कोण्डागांव के बड़ेबेन्दरी, माकड़ी की कन्या आश्रम माकड़ी एवं केशकाल की सुरडोगर, बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड की भद्रकाली एवं मद्देड़ भैरमगढ़ की बेंगलुर एवं भैरमगढ़, बस्तर जिले की बस्तानार विकासखंड के करकापारा एवं विकासखण्ड बकावंड के चिरउगांव के पूर्व माध्यमिक शाला नवीन भवन निर्माण शामिल है। कांकेर जिले की नरहरपुर विकासखंड के बासनवाही एवं अंतागढ़ विकासखंड के तुमसनार तथा कोयली बेड़ा के पोरोण्डी, सुकमा जिले की छिंदगढ़ विकासखंड के बिरसठपाल एवं पाईकपारा गोरली, दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के पाहुरनार पूर्व माध्यमिक शाला नवीन भवन निर्माण शामिल है। कोरबा जिले की सीतामणी एवं पहंदा, सूरजपुर जिले की प्रतापपुर विकासखंड के पण्डोपारा बरपटिया एवं गोविंदपुर तथा सरगुजा जिले की मैनपुर विकासखंड के जामडीह एवं लुण्ड्रा विकासखंड के रघुपुर एवं करगीडीह पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। इन सभी शालाओं के लिए प्रति पूर्व माध्यमिक शाला के नवीन भवन निर्माण के लिए 11.84-11.84 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। इसी क्रम में 32 प्राथमिक शालाओं के नवीन भवन निर्माण हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें जिला जशपुर के विकासखण्ड मनोरा की गौवारू, बगीचा की पण्डरूटोली, इचौली एवं सोनमुठ, विकासखण्ड दुलदुला के टेढ़ापहाड़, फरसाबहार के बागमाड़ा, कुनकुरी के कोरवाडेरा एवं डडगांव, पत्थलगांव के नया केकियाखार, टोंगरीपारा एवं जगलपारा प्राथमिक शाला नवीन भवन निर्माण शामिल है। इसी प्रकार विकासखण्ड कांसाबेल के केन्दुटोला, कन्या आश्रम कांसाबेल एवं गरईबंध, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर जिले के ठिसकोली, कोण्डागांव जिले के बरकई, कांकेर जिले के करेंगांव तथा सुकमा जिले के रतिनाईकरास में प्राथमिक शाला नवीन भवन निर्माण शामिल है। बीजापुर जिला के भैरमगढ़ विकासखंड के बेलनार, भोपालपटनम विकासखंड के बंदेपारा एवं कोरेजेड तथा बस्तर जिला के बस्तानार विकासखंड अंतर्गत ककरापारा एवं कापानार शामिल है। इसी प्रकार गरियाबंद जिला के गरियाबंद विकासखंड अंतर्गत हथोड़ाडीह एवं मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ताराझर, सूरजपुर जिला अंतर्गत गवाटियापारा, कोरबा जिला के करतला विकासखंड के सीधरामपुर तथा पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के चंदनपुर, बलरामपुर के कपौत तथा रायगढ़ के खरसिया विकासखंड के भूदेवपुर शामिल है। प्रत्येक प्राथमिक शाला नवीन भवन निर्माण के लिए 11.48-11.48 लाख रूपए की स्वीकृति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भूमि आबंटन के पश्चात भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तथा सभी कार्यों का व्यय विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इन निर्माण कार्यों से अनुसूचित जनजाति बहुल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ होंगी।

किसानों के हित में राज्य सरकार का अहम निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में किसानों के हित और मांग को ध्यान में रखकर धान खरीदी की तिथि में दो दिवस की वृद्धि का अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर अब राज्य शासन द्वारा आगामी दो दिवस 4 और 5 फरवरी को राज्य के ऐसे किसान जो पंजीकृत है और जिनका टोकन कट चुके है, उन किसानों का धान खरीदा जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के वास्तविक किसानों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान खरीदी केन्द्रों में पारदर्शी व्यवस्था शुरू की थी जो सार्थक सिद्ध हुआ है। उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर 2025 से शुरू धान खरीदी का महाभियान के तहत 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख 11 हजार से अधिक किसानों से लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को 33 हजार 149 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। सरकार द्वारा धान खरीदी की तिथि बढ़ाये जाने से अब उन छूटे हुए किसान भी सुगमतापूर्वक अपना धान बेच सकेंगे। इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था और किसान-हितैषी व्यवस्था से किसानों के हितों की रक्षा के साथ ही वास्तविक किसानों को लाभान्वित करने का संकल्प सार्थक हो रहा है। राज्य में इस खरीफसीजन के लिए 27 लाख 43 हजार 145 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेशभर में संचालित सभी 2,740 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, डिजिटल निगरानी युक्त और पूर्णतः पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है। शासन की यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि वास्तविक किसान को ही लाभ मिले और बिचौलियों अथवा फर्जी प्रविष्टियों की कोई गुंजाइश न रहे।

संपादकीय

न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि

समस्या आनुपातिक समानता के नाम पर दशकों से चल रही वो राजनीति है, जिसमें न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि दे दी गई है। इस सोच ने समाज को पुरानी जकड़नों में और भी मजबूती से बांध डाला है। उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों ने नई सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। इससे संबंधित अपने आरंभिक ड्राफ्ट में आयोग ने दो बदलाव किए। उससे ये मामला भड़का है। शुरुआती ड्राफ्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शामिल थी। उसमें यह प्रावधान भी था कि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र (या कर्मचारी) पर क्या कार्रवाई होगी। ड्राफ्ट का समाज के एक हिस्से की तरफ से विरोध हुआ। उसके दबाव में आकर यूजीसी ने एक तो संभावित उत्पीड़न का शिकार होने वाले समूहों में ओबीसी जातियों को शामिल कर दिया और दूसरे गलत शिकायत से संबंधित प्रावधान को हटा दिया। नतीजा सामान्य श्रेणी वर्ग में गहरे असंतोष के रूप में सामने आया है। इन समूहों की दलील है कि जाति आधारित भेदभाव का शिकार वो भी होते हैं। इस समझ के मुताबिक जातिगत भेदभाव ताकत एवं प्रभाव की स्थिति में मौजूद हर अधिकारी कर सकता है, भले वह किसी जाति से आया हो। उनके मुताबिक यूजीसी इक्विटी विनियमन 2026 की भाषा ऐसी है, जिससे संदेश जाता है कि हर मामले में उत्पीड़क सामान्य श्रेणी के लोग ही होते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूजीसी इस तर्क से सहमत नहीं है और जल्द ही वह इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करेगा। अगर ये खबर सच है, तो अपेक्षित होगा कि यूजीसी फौरन ऐसा करे। वरना, ये विवाद एक नई सामाजिक अशांति का कारण बनता नजर आ रहा है। वैसे, इस तरह के मामलों में तमाम तरह के स्पष्टीकरणों की अपनी सीमा है। समस्या आनुपातिक समानता के नाम पर दशकों से चल रही वो राजनीति है, जिसमें न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि दे दी गई है। इस सोच ने समाज को पुरानी जकड़नों में और भी मजबूती से बांध डाला है। चूंकि इस सोच में जाति के अलावा पिछड़ेपन, शोषण, एवं भेदभाव के कहीं अधिक मूलभूत दूसरे कारणों को सिरे से नजरअंदाज किया गया है, इसलिए जकड़नों को तोड़ कर आगे बढ़ने की दृष्टि और सामाजिक प्रगति के रास्ते बाधित हो गए हैं।

भारत को तुर्की से सीखना चाहिए

हरिशंकर व्यास

भारत के सामने एक मॉडल तुर्किए का है, जिसने न सिर्फ अपने को अपनी हथियार जरुरतों में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों को ड्रोन सहित अपने हथियार बेच रहा है। उसने पिछले 40 साल में इतने सुनियोजित तरीके से यह काम किया है कि भारत को उससे सीखना चाहिए। भारत ने भी देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्किए से मिले ड्रोन से पाकिस्तान लड़ रहा था। अब भी उसी के ड्रोन गाहे बगाहे पाकिस्तान सीमा पर दिखते हैं। उसने सातवें दशक में साइप्रस संकट के समय अमेरिका और यूरोप ने उसको हथियार देने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद ही उसने अपने को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया और 1985 में प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाम से एक केंद्रीय संस्था बनाई। उसके बाद पिछले चार दशक में तुर्किए ने अलग ही पहचान बना ली है। भारत भी इस मॉडल पर काम कर सकता है। इस मॉडल की कुछ खास बातें हैं। जैसे तुर्किए ने दूसरे देशों के साथ जो भी हथियार सौदा किया उसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अनिवार्य शर्त रखी। उसने अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि से हथियारों का सौदा किया तो उसके लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखी। उसने स्थानीय इंजीनियरों द्वारा उत्पादन की भी शर्त रखी। सोर्स कोड और डिजाइन पर अधिकार किया और लडाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइल जैसी कई चीजों के उत्पादन का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद उसने ड्रोन क्रांति की, जिसमें निजी कंपनियों को शामिल किया। रक्षा उत्पादन में भी तुर्किए ने पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया। लेकिन ड्रोन का पूरा क्षेत्र निजी कंपनियों को दिया और यह सुनिश्चित किया कि वे उत्पादन करें, बिकवाने की गारंटी उसकी होगी। यानी तुर्किए उनके लिए बाजार और ग्राहक जुटाएगा। आज स्थिति यह है कि अपनी रक्षा जरुरतों के मामले में तुर्किए 80 फीसदी आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं तुर्किए आज 180 देशों को अपने हथियार बेचता है। पूरा अफ्रीका उसका बाजार है। वह मध्य एशिया, खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप को भी हथियार बेचता है। उसने देश के कई हिस्सों में डिफेंस प्रोडक्शन के कलस्टर बनाए हैं, जहां उत्पादन होता है। भारत अगर आज इस मॉडल पर चलना शुरू होता है तो अब तकनीक और उत्पादन की रफ्तार दोनों इतनी तेज हो गई है कि उसे तुर्किए की तरह 40 साल नहीं इंतजार करना होगा। वह सिर्फ 10 साल में अपनी जरुरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और दुनिया के रक्षा से जुड़े उत्पाद बेचने लगेगा। भारत के पास पहले से डीआरडीओ और अन्य पीएसयू हैं, जो रक्षा उपकरण बना रहे हैं। भारत जो व्यापारिक संधियां कर रहा है उसमें प्रौद्योगिक हस्तांतरण, लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, लोकल इंजीनियर और लोकल प्रोडक्शन, सोर्स कोड व डिजाइन पर कंट्रोल आदि की शर्तें रखवाता है और निजी व सरकारी कंपनियों को इस काम में शामिल करता है तो बहुत जल्दी भारत में भी एक बड़ा मिलिट्री डिफेंस कॉम्प्लेक्स विकसित हो सकता है। इसके अलावा भारत के पास इसरो के रूप में एक ऐसी संस्था है, जिसने पहले से पूरी दुनिया में अपना बाजार बनाया है। उसको राजनीति में घसीटने की बजाय उसे और मजबूत बनाया जाए तो वहां से दुनिया भर के सेटेलाइट लॉन्च होंगे, जिनसे भारत को आय होगी। भारत की बड़ी समस्या यह है कि यहां के अरबपति, खरबपति सब यही के 140 करोड़ लोगों की जेब से पैसे निकालने और सरकारी व प्राकृतिक संपदा का दोहन करके अपना खजाना भरने में लगे हैं। वे शोध व विकास यानी आरएंडडी पर धेला खर्च नहीं करते हैं। वे कोई जोखिम नहीं लेते हैं। उनकी सारी कमाई दुनिया की बड़ी कंपनियों का माल बेच कर है या सरकारी ठेके हासिल करने से है। सरकार खुद भी आरएंडडी पर बहुत कम खर्च करती है। सरकार रिसर्च पर अपना खर्च बढ़ाए, शिक्षण संस्थाओं को बेहतर करे और निजी सेक्टर को निवेश करने के लिए प्रेरित करे तब भी भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और उसके बाद भारत अपना सामान बाहर बेचने लायक बनेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

ललित गर्ग

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां देर आए, दुरुस्त आए की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया।

50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं। यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को निरंतर धैर्य का परिणाम बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाज़ी अक्सर महंगी पड़ती है। अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका।

यदि वाशिंगटन भारत पर एकतरफा दबाव बनाए रखता, तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। ट्रंप द्वारा 500 अरब डॉलर के आयात, शून्य टैरिफ और रूसी तेल त्यागने जैसे नाटकीय दावे इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थे, जिन्हें भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव का मुद्दा बनाया और न ही स्वीकारोक्ति दी। मोदी का इन पर मौन यह दर्शाता है कि भारत इस घटनाक्रम को अंतिम समझौते के रूप में नहीं, बल्कि दिशा-निर्धारण के रूप में देख रहा है। इसके विपरीत, भारतीय विपक्ष इस पूरे प्रकरण में अपनी राजनीतिक अधीरता और रणनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता रहा। उसने टैरिफ को लेकर तात्कालिक लाभ-हानि की भाषा में सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं समय, धैर्य और बहुस्तरीय गणनाओं की मांग करती हैं। विपक्ष यह समझने में असफल रहा कि कूटनीति में कभी-कभी पीछे हटना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। आज जब अमेरिका को अपना अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा है और भारत फिर से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिख रहा है, तब यह स्पष्ट है कि मोदी की नीति न केवल दबाव से मुक्त थी, बल्कि दूरदर्शी भी। यही नीति भारत को एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सौदे की शर्तें तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह वैश्विक व्यापार में दबाव आधारित राजनीति के अंत का संकेत देता है। लंबे समय से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ, प्रतिबंध और नीतिगत दबावों के माध्यम से छोटे या उभरते देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश करती रही हैं। भारत ने इस प्रवृत्ति को न केवल चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आत्मविश्वास, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी दबाव को संतुलित संवाद में बदला जा सकता है। भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में यह समझौता एक नए राजनीतिक आभामंडल के निर्माण का भी संकेत देता है। यह संबंध अब केवल रणनीतिक या सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक साझेदारी के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में बहुध्रूवीय व्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा। दुनिया धीरे-धीरे यह स्वीकार कर रही है कि भविष्य का नेतृत्व किसी एक शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि संतुलित साझेदारियों के माध्यम से उभरेगा, और भारत उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस व्यापारिक प्रगति से मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह साख किसी प्रचार या दावे पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित है। भारत आज विश्व मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्थिरता और सहयोग में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। यही संतुलन उसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग पहचान देता है। महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा भावनात्मक नारों पर नहीं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों, रणनीतिक समझौतों और वैश्विक स्वीकार्यता पर आधारित है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते उस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत को आगे बढ़ने से रोक पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्यापारिक समझौता भारत की परिपक्व कूटनीति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनिया में कोई भी निर्णय केवल आर्थिक गणित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और नेतृत्व की परिपक्वता का भी प्रमाण होता है। देर से लिया गया सही निर्णय, जल्दबाजी में किए गए गलत समझौतों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भारत ने धैर्य रखा, आत्मसम्मान बनाए रखा और अंततः अपने हितों के अनुरूप परिणाम हासिल किया। निश्चित ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सुरक्षित है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है और यह विश्वास ही उसे महाशक्ति बनने की उड़ान देता है।

शिक्षक अब पाठ्येत्तर कार्यों के लिए हैं

अजीत द्विवेदी

शिक्षक का मूल कार्य अध्ययन और अध्यापन है। भारत के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अध्ययन का काम पहले ही काफी हद तक छोड़ चुके थे और अब अध्यापन का काम भी नाममात्र का रह गया है। शिक्षक अब स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि पाठ्येत्तर कार्यों के लिए हैं। उनके ऊपर इतने कामों की जिम्मेदारी लाद दी गई है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर लगातार कम होता जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं या शिक्षकों के प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वह कई कारणों में से एक कारण है। असल में सरकारी स्कूलों की कार्यों की सूची में अध्यापन का कार्य प्राथमिकता में नहीं है।

उन्हें स्कूल से बाहर और स्कूल में भी कई दूसरे काम करने हैं, जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के शिक्षक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में लगे हैं। कुछ राज्यों के शिक्षक स्थानीय निकायों के चुनाव करा रहे हैं। इस साल और अगले साल दो चरणों में जनगणना का काम होगा और शिक्षक उसमें लगा दिए जाएंगे। पांच राज्यों के चुनाव भी हैं तो मतदान कराने से लेकर मतगणना तक उन राज्यों के सरकारी शिक्षक उसमें व्यस्त हो जाएंगे। वैसे उन राज्यों के स्कूल भी चुनाव के लिए आरक्षित होंगे। कहीं सुरक्षा बलों को ठहराया जाएगा तो कहीं मतदान केंद्र बनेंगे तो कहीं मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण या मतदान और मतगणना या जनगणना जैसे कामों की सूची बेहद लंबी है, जो शिक्षकों को करना होता है। एक अनुमान के मुताबिक अध्ययन और अध्यापन के अलावा शिक्षकों को स्कूल के बाहर डेढ़ दर्जन किस्म के अन्य सरकारी काम करने होते हैं। एक शिक्षक ने तंज करते हुए सोशल मीडिया में लिखा था कि अच्छा है कि सरकार खेती नहीं कराती है अन्यथा बुवाई, कटाई का काम भी शिक्षकों को करना होता।

बहरहाल, सरकार परिवार और स्वास्थ्य का सर्वे करती है तो वह काम शिक्षक करते हैं, सरकार पशुओं की गिनती कराती है तो वह काम शिक्षक करते हैं, सरकार किसी आपदा की स्थिति में राहत सामग्री बांटती है तो वह काम भी शिक्षकों के जिम्मे होता है, किसी बीमारी या टीके के लिए जागरूकता फैलानी है तो उसका जिम्मा भी शिक्षकों के ऊपर होता है, सफाई अभियान चलाना है तो उसमें शिक्षकों को आगे किया जाता है, यहां तक कि सत्तापक्ष के किसी बड़े नेता की रैली होती है तो उसमें भी शिक्षकों को बस में भर कर रैली में जाना होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा जिले के कलेक्टर, प्रखंड के बीडीओ और पंचायत के मुखिया भी शिक्षकों को किसी न किसी काम में लगाए रहते हैं।

स्कूल के बाहर शिक्षकों को जो डेढ़ दर्जन अलग अलग किस्म के काम करने होते हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि बचे हुए समय में उनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। स्कूल में उनको डेढ़ दर्जन अलग किस्म के काम करने हैं, जो अध्ययन और अध्यापन से इतर हैं। मिसाल के तौर पर मिड डे मील तैयार करना एक काम होता है। एक से ज्यादा शिक्षक तो इसी में लगे रहते हैं। राशन खरीदने से लेकर खाना तैयार कराना और बच्चों को खिलाना स्कूलों में प्राथमिकता का काम है। जब से सरकार को लगने लगा है कि मास्टर लोग राशन में गड़बड़ी करते हैं तब से गड़बड़ी नहीं होने के सबूत जुटाना यानी हर चीज का हिसाब रखना, वीडियो आदि बनाना, डैशबोर्ड पर अपलोड करना भी शिक्षकों का जिम्मा हो गया है।

एक समय सरकार को लगा कि बच्चे सिर्फ खाने आते हैं या बच्चों की असली संख्या कम होता है और ज्यादा बच्चों के लिए खाना बनाने के नाम पर पैसे की गड़बड़ी होती है तब से शिक्षकों को यह काम भी दिया गया कि वे मिड डे मील खाने वाले बच्चों का फेशियल रिकग्निशन करें और उनकी वीडियो तैयार करें ताकि पुष्टि हो सके कि जिस बच्चे का नाम रॉल में है उसने स्कूल में खाना खाया। सो, मिड डे मील का मामला अब राशन खरीदने, खाना बनवाने और खिलाने के काम से काफी आगे बढ़ गया है। इस बीच तमिलनाडु सहित 12 राज्यों ने प्रस्ताव दिया है कि अगर स्कूलों में बच्चों को सुबह का नाश्ता भी दिया जाए तो उनका बेहतर पोषण होगा, उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसे भी लागू कर ही देना चाहिए ताकि शिक्षकों को पढ़ाने के काम से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए।

ऐसा नहीं है कि इतने पर भी शिक्षकों की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उन्हें और भी कई काम करने होते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री शिक्षा से जुड़े किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं तो स्कूलों से कहा जाता है कि उनका भाषण बच्चों को सुनाया जाए ताकि वे 'लाभान्वित' हो सकें। केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनाया जाता है तो राज्यों के स्कूलों में राज्य के शिक्षा मंत्री का भाषण सुनाया जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण तो सभी स्कूलों में सुनाया जाता है। भाषण सुनाने की व्यवस्था करने में कम से कम दो कक्षाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन इतने पर काम खत्म नहीं होता है।

भाषण सुनते बच्चों की वीडिया बना कर उनको ऊपर भेजना होता है और किसी निर्धारित पोर्टल पर अपलोड भी करना होता है। यह काम हर सरकारी फंक्शन के बाद करना होता है। राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम हो या नवाचार के नाम पर शुरू की गई किसी पहल का कार्यक्रम हो। उसे आयोजित करना, उसकी वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। शिक्षकों को इवेंट मैनेजर बना दिया गया है। उनको कार्यक्रम आयोजित करने, उसे सफल बनाने और उसके वीडियो अपलोड करने से फुरसत नहीं मिलती है। ग्रामीण और छोटे कस्बों में तो ज्यादातर स्कूल दो या तीन शिक्षकों के साथ चलते हैं। उन स्कूलों में तो शिक्षकों को पढ़ाने की फुरसत कभी नहीं मिल पाती है।

एनसीईआरटी के निदेशक रहे देश के जाने माने शिक्षाविद् प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दो महीने पहले 'एक अंग्रेजी अखबार' में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'इन इंडिया, व्हाई टीचर्स आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द क्लासरूम'। इसमें उन्होंने यूनेस्को की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसका टाइटल 'व्हेअर हैव ऑल द टीचर्स गॉन' था। इसमें यूनेस्को ने दुनिया भर में उभर रहे एक ट्रेंड का हवाला दिया था। दुनिया भर के देशों में पिछले दो दशक में अलग अलग कारणों से शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी नौकरी मिलने पर वे शिक्षक की नौकरी छोड़ रही हैं। वे स्कूलों में नौकरी करने की बजाय बेरोजगारी और अनिश्चितता का भविष्य चुन रहे हैं। यह बहुत भयावह ट्रेंड है। ऐसा करने के कई कारणों में एक कारण स्कूलों में बच्चों का बदलता व्यवहार भी है।

अच्छे शिक्षकों के लिए अब बच्चों को स्कूलों में हैंडल करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। एक कारण स्कूलों की दशा भी है। लेकिन एक बड़ा कारण नौकरशाही है, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा प्रबंधन के काम में लगा दिया गया है। उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने हैं, कार्यक्रमों की वीडियो बनानी है, उन्हें सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना है, अलग अलग कार्यों की रिपोर्ट तैयार करनी है, उस रिपोर्ट को सरकारी दफ्तरों में भेजना है, नेताओं व अधिकारियों के भाषण सुनने हैं, उन भाषणों में कही गई उलजुलूल बातों को स्कूल में बच्चों को बताना है, इन सब कारणों से अच्छे शिक्षकों का मोहभंग हो रहा है। वे स्कूल छोड़ रहे हैं। जो बचे रह जा रहे हैं वे अध्ययन या अध्यापन का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी कर रहे हैं।

जिसका पहले विरोध वही बाद में सही कैसे.....

सुनील दास

राजनीति में कई बार ऐसा होता है और चर्चा का विषय बन जाता है जब आप सत्ता में नहीं होते हैं और जिस काम का विरोध करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद आप वही करते हैं जिसे कभी आपने खुद गलत मानकर विरोध किया था।ऐसे में लोग तो सवाल करेंगे ही कि पहले जो आपके लिए गलत था, उसी को आज सही कैसे मान रहे हैं और वैसा काम क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि जो काम पहले गलत था, वह आज भी गलत है, जो काम पहले आपके लिए गलत था वह आज सही कैसे हो सकता है, क्या इसलिए सही हो सकता है कि आज आप सत्ता में है और आप फैसला कर सकते हैं। ऐसे काम का विरोध तो होगा ही और गलत है तो उसे वापस लेना पड़ेगा ही। रायपुर की महापौर को अपने फैसले से पीछे हटना इसीलिए पड़ा है क्योंकि वह पहले जिस गलत बता रही थी, उसे आज वह सही मान रही थी। कांग्रेस के विरोध के चलते उनको मानना पड़ा कि वह गलत कर रही थीं।

.यह तो शहर के सारे लोगों को याद है कि तेलीबांधा तालाब के किनारे गाडियां खड़ी करने पर पार्किंग ठेका का जब 21-22 में दिया गया था तो भाजपा पार्षदों ने विरोध कर इसे रद्द कराया था। उसी जगह पर पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए बिना किसी ठेके के दरें तय करने तख्तियां टांग दी गईं।सबसे पहले तो निगम के इस फरमान का घूमने आने वालों ने विरोध किया।इस विरोध के चलते महापौर ने शनिवार को सुबह तेलीबांधा किनारे का दौरा करके यहां सुबह घूमने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया था और तालाब किनारे स्थित होटलों में आने वालों, अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वालों से शुल्क लेने के जायज ठहराया था। महापौर का यह आदेश निगम के कर्मियों को ही हैरान करने वाला था कि वह वह यह कैसे तय करेंगे कि कौन घूमने आया है और कौन होटल में खाने या बेठने आया है।

तेलीबांधा तालाब के किनारे पार्किंग शुल्क पर भाजपा के दोहरे मापदंड का विरोध कांग्रेस नेताओं को करना ही था,उनके लिए यह ऐसा मौका था जिसके आधार पर महापौर का गलत ठहरा सकते थे। इसलिए पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने महापौर के फैसले का विरोध किया और कहा कि इसके खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी।एक फरवरी को मरीन ड्राइव के निजीकरण व व्यवसायीकरण के विरोध में मरीन ड्राइव में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और महापौर से आदेश वापस लेने की मांग भी की। साथ ही कहा गया कि यदि निगम प्रशासन ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी।इसका परिणाम यह हुआ कि एक फरवरी की शाम महापौर ने पार्किंग मामले में यूटर्न लिया और कहा कि सड़क पर खड़ी गाड़ी से पार्किंग शुल्क कैसे लिया जा सकता है।निगम के पास तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां नागरिक अपनी गाडी पार्क कर सकें इसलिए 15 दिन तालाब किनारे बैठने व घूमने वालों की मानिटरिंग की जाएगी,सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से रोकने का अधिकार निगम के पास नहीं है, इसलिए निगम की एक बैठक पुलिस के साथ होगी। यानी महापौर ने स्वीकार किया कि वह जो करने जा रही थी वह उनका अधिकार नहीं है।इससे तो साफ हो गया है कि महापौर जो करने जा रही थी, वह गलत था। यह बात भी सभी जानते हैं कि सड़क पर यातायात पुलिस ही पार्किंग का एरिया तय करती है। यह यातायात पुलिस का अधिकार है कि वह किसी सड़क पर पीली लाइन खींचकर पार्किंग एरिया तय करे।अगर पीली लाइन से बाहर गाड़ी खड़ी की जाती है तो जुर्माना की चेतावनी दी जाती है और जुर्माना भी किया जाता है।यह व्यवस्था जयस्तंभ चौक किनारे रवि भवन, एमजी रोड़ सहित कई सड़कों पर लागू है।

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन करें भगवान गणेश की पूजा

सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। क्योंकि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। फाल्गुन माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा और व्रत किया जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा और व्रत के साथ-साथ चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कल 5 फरवरी को मध्यरात्रि 12 बजकर 9 मिनट पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 6 फरवरी को मध्यरात्रि 12 बजकर 22 मिनट पर हो जाएगा। सनातन धर्म में उदयातिथि मानी जाती है। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 फरवरी 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय का समय :-

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने पर ही व्रत पूर्ण होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन रात 09 बजकर 35 मिनट पर चंद्रोदय होगा। इस समय पर आप चंद्र देव की पूजा कर सकते हैं।

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगा। ये मुहूर्त 06 बजकर 15 मिनट रहेगा। शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 07 बजकर 07 मिनट पर शुरू होगा। ये मुहूर्त 08 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर शुरू होगा। ये मुहूर्त 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। लाभ-उन्नति मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगा। ये मुहूर्त 01 बजकर 57 मिनट तक रहेगा।

काली मुद्रा करने से क्या होता है लाभ

क्या आपको भी लाइफ में मन का अशांत होना, डर, घबराहट, नींद न आना और तनाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल, काम का दबाव और भविष्य की चिंता - ये सब बातें क्या आपको भी अंदर से थका रही हैं। ऐसे में आयुष मंत्रालय योग करने की सलाह देता है। जरूरी नहीं कि आप मुश्किल वाले आसन करें। आसान सी हस्त मुद्रा भी आपको इन परेशानियों से निपटने में सहयोग देगी। इसी में शामिल है काली मुद्रा, जिसे करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बना रहता है।

काली मुद्रा कैसे करते हैं

काली मुद्रा का अभ्यास करना बहुत आसान है। इसे सुखासन में बैठकर या ताड़ासन में खड़े होकर किया जा सकता है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर तर्जनी उंगलियों को ऊपर की ओर सीधा रखा जाता है। सांस को धीरे-धीरे अंदर लें और बाहर छोड़ते समय मन में नकारात्मक विचारों को छोड़ने का भाव रखें। शुरुआत में दो से तीन मिनट पर्याप्त हैं। बाद में समय बढ़ाया जा सकता है।

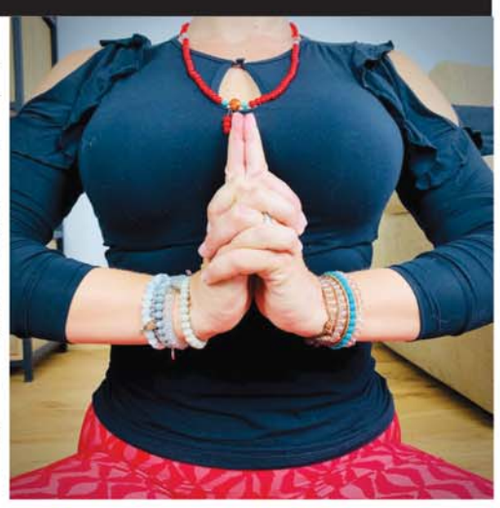

आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार

आयुष मंत्रालय के अनुसार, काली मुद्रा शरीर को अंदर से ताकतवर बनाती है। यह मुद्रा मन के बोझ को हल्का करने, नकारात्मक सोच को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। योग शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर में ऊर्जा के बहाव के लिए नाड़ियां होती हैं। इनमें से सुषुम्ना नाड़ी सबसे मुख्य मानी जाती है, जो रीढ़ के बीच से होकर गुजरती है। जब इस नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहता है, तो मन शांत रहता है और शरीर संतुलन में रहता है। काली मुद्रा इसी ऊर्जा प्रवाह को साफ और सक्रिय करने में सहायक मानी जाती है। नियमित अभ्यास से मन की उलझनें कम होती हैं और ध्यान लगाने में आसानी होती है। शारीरिक रूप से काली मुद्रा सांस की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। गहरी सांस लेने और छोड़ने से फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का संचार अच्छा होता है। इससे शरीर में जकड़न और थकान कम होती है। लंबे समय तक बैठे रहने या तनाव के कारण अकड़न से भी धीरे-धीरे राहत मिलती है। रक्त संचार बेहतर होने से शरीर हल्का महसूस करता है।

काली मुद्रा का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो काली मुद्रा का प्रभाव काफी गहरा माना जाता है। आजकल बच्चे हों या बड़े, सभी किसी न किसी मानसिक दबाव में रहते हैं। यह मुद्रा दिमाग में छाए धुंधलेपन को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती है। पढ़ाई करने वाले बच्चों और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह लाभकारी मानी जाती है।

भावनात्मक स्तर पर काली मुद्रा डर, गुस्सा और बेचैनी जैसी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन हल्का होता है और भावनाओं का संतुलन बनता है। व्यक्ति खुद को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित महसूस करता है।

दिन शुरू करने से पहले दिमाग को ऐसे करें रीसेट

अक्सर हम दिन की शुरुआत अलार्म की आवाज, जल्दबाजी और अधूरे विचारों के साथ करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह समय तय करता है कि आपका दिमाग, शरीर और भावनाएं पूरे दिन कैसे काम करेंगी। जिस तरह खाली पेट हम गलत खाना खा लें तो पाचन बिगड़ जाता है, उसी तरह सुबह उठते ही अगर दिमाग को गलत सोच, जल्दबाजी और आत्म-आलोचना से भर दिया जाए तो मानसिक संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। सुबह के पहले 10-15 मिनट आपके पूरे दिन के हार्मोन, मूड और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्म-विश्वास की नींव है।

सुबह उठते ही खुद से कही गई बातें आपके दिमाग को दिशा देती हैं। पहला रिमाइंडर होना चाहिए- 'मैं जितना सोच रहा/रही हूं, उससे बेहतर कर रहा/रही हूं।' इससे अनावश्यक सेल्फ-क्रिटिसिज्म कम होता है।

इसके बाद यह याद दिलाना जरूरी है कि एक अच्छी आदत आज भी हार्मोन बैलेंस कर सकती है- जैसे गहरी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग या पानी पीना।

कई लोग अपने शरीर को 'फेल' समझने लगते हैं, जबकि सच यह है कि शरीर संकेत दे रहा होता है। इसलिए सुबह खुद से कहें- 'मेरा शरीर कमजोर नहीं, सपोर्ट मांग रहा है।' यह सोच हीलिंग की शुरुआत करती है।

मोटिवेशन की जगह प्लान पर फोकस करना भी एक अहम मॉर्निंग मंत्र है। 'मुझे मोटिवेशन नहीं, एक स्पष्ट योजना चाहिए— यह वाक्य आपको पूरे दिन भटकने से बचाता है।

साथ ही, खुद को यह अनुमति देना कि आप 'वर्क इन प्रोग्रेस' हैं और फिर भी खुद पर गर्व कर सकते हैं, मानसिक दबाव कम करता है।

दिन में कुछ भी हो, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता आपके हाथ में है। सुबह यह दोहराना कि 'मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से जवाब दूंगा/दूंगी- आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

यह याद दिलाना भी बेहद जरूरी है कि आज का हर छोटा कदम भविष्य की ताकत बना रहा है।

मेरे पास देने के लिए कुछ कीमती है और इसकी शुरुआत खुद का ख्याल रखने से होती है। सेल्फ-केयर स्वार्थ नहीं, बल्कि बुनियाद है।

बच्चे की पैरेंटिंग में खास रोल निभाते हैं ये बेसिक मैनर...

बच्चों की परवरिश करना आसान काम नहीं है। काफी सारे बेसिक मैनर उन्हें बचपन से ही सिखाने होते हैं। क्योंकि इन्हीं मैनर पर बच्चे के व्यवहार की नींव होती है। जिससे पता चलता है कि आगे चलकर बच्चा लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपने काम खुद से करना सीखेगा या नहीं। अपने बढ़ते बच्चे को हर दिन इन बेसिक मैनर का पाठ जरूर पढ़ाएं। जान लें कौन से बेसिक एटिकेट हैं जिन्हें बच्चे को जरूर सिखाने चाहिए।

थैंक्यू बोलने की आदत

अपने बच्चे को थैंक्यू बोलने की आदत डलवाएं। बगैर आपके याद दिलाए बच्चे को पता होना चाहिए कि आखिर कब उसे लोगों को थैंक्यू बोलना है। ऐसा करने से बच्चे के अंदर ग्रेटीट्यूड की फीलिंग आती है। हर इंसान के काम में उसे वैल्यू दिखती है और वो उस वैल्यू को एप्रिसिएट करना सीखता है।

खाने के बाद प्लेट को सिंक में रखना

बच्चे को ये हैबिट बचपन से ही लगानी चाहिए। उसे जरूर सिखाएं कि खाने के बाद अपनी प्लेट को उठाकर सिंक में रखते हैं। ये बेसिक मैनर खाने की रिस्पेक्ट करना बच्चे को सिखाएगी। बच्चा अपने प्लेट में खाना कम से कम छोड़ेगा क्योंकि वो खुद से देख सकेगा कि खाने की बर्बादी हो रही है और धीरे-धीरे बच्चा सीख सकेगा कि इसे कैसे रोकना है।

बच्चे को सफाई करना सिखाएं

बचपन से ही बच्चे को सिखाएं कि गंदगी फैलाने के बाद उसकी सफाई खुद से करें। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे सारे ट्वॉय कलेक्ट करके रखने को बोलना जरूरी है। जिससे बच्चा बड़ा होकर सीख पाएगा कि सफाई कैसे रखना है। इससे आपका काम भी आसान होगा।

काली मिर्च खाने के कई सारे फायदे

काली मिर्च खाने के कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन इसे किस तरह खाना है ये तो न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकते हैं। लीमा महाजन ने शेयर किया कि किन 6 चीजों में मिलाकर एक चुटकी काली मिर्च खाने से फायदा होगा। फायदे के लिए एक चुटकी काली मिर्च ऐसे खाएं

■ आयुर्वेद में दवा की तरह इस्तेमाल

काली मिर्च केवल मसाला नही है बल्कि ये आयुर्वेद में दवा की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसमे पाया जाने वाला पैपरीन कंपाउंड हेल्थ के लिए पावरफुल इंग्रीडिएंट का काम करता है। लेकिन काली मिर्च को किस तरह से डाइट में शामिल करें कि इसके सारे फायदे मिले?

■ दही में एक चुटकी काली मिर्च

दही खाते समय अगर एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर खाया जाए तो दही ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट होती है और ब्लोटिंग नहीं होती।

शहद में एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर खाएं

एक चम्मच शहद में एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाने से खांसी और गले की खराश में आराम मिलता है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन कंपाउंड म्यूकस को साफ करने में मदद करता है।

■ नींबू पानी में एक चुटकी काली मिर्च

नींबू पानी में काली मिर्च एक चुटकी मिलाकर खाना खाने के पहले पिया जाए तो इससे डाइजेशन एंजाइम्स को बढ़ाता है। जिससे खाना आसानी से पचता है।

■ आंवला के जूस में एक चुटकी काली मिर्च

आंवला के जूस में एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिया जाए तो इससे विटामिन सी का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। पाइपरिन कंपाउंड विटामिन सी को ब्लडस्ट्रीम में तेजी से ले जाने में मदद करता है।

■ हल्दी के साथ काली मिर्च

हल्दी के साथ काली मिर्च को एक चुटकी मिलाकर पिया जाए तो हल्दी के पूरे फायदे मिलते हैं। काली मिर्च हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को अब्जॉर्ब करने में ज्यादा मदद करती है।

वेजिटेबल सैंडविच

वेजिटेबल सैंडविच एक बहुत ही आसान, हेल्दी और जल्दी बनने वाला स्नैक है। इसलिए जल्दबाजी में भूख मिटाने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही, इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डालकर बना सकते हैं, जिससे यह हेल्दी भी होता है। आइए जानें वेजिटेबल सैंडविच बनाने की रेसिपी।

सामग्री :

8 ब्रेड स्लाइस, 1/2 कप बारीक कटा हुआ खीरा,1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर,1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च,1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज,4 बड़े चम्मच मेयोनीज या हरी चटनी,स्वादानुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर,1/2 चम्मच चाट मसाला,2-3 बड़े चम्मच मक्खन या बटर

विधि :

सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लें और उसमें बारीक कटी हुई सभी सब्जियां (खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज) डाल दें। अब सब्जियों में मेयोनीज या हरी चटनी डालें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। ध्यान दें कि सब्जियों में नमक सबसे लास्ट में डालें ताकि वे पानी न छोड़ें।

ब्रेड के दो स्लाइस लें। अगर आप सैंडविच को सेकना चाहते हैं, तो ब्रेड के बाहरी किनारों पर हल्का मक्खन लगा लें। अब तैयार सब्जी को ब्रेड के एक स्लाइस पर अच्छी तरह फैलाएं। ऊपर से दूसरा स्लाइस रखकर सैंडविच बंद कर दें। सैंडविच को ग्रिलर या टोस्टर में रखें और कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक ग्रिल करें। गरमा-गरम सैंडविच को केचअप या चटनी के साथ सर्व करें।

भारतीय सनातन संस्कृति का गौरवगान

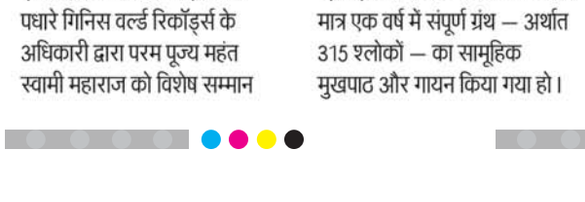

वडोदरा में 2 फरवरी 2026 को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयन्ती महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्यता और गहन भक्तिभाव के साथ किया गया। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की वाणी, प्रभाव, अहं-शून्यता और उच्च आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाने वाली विशेष वीडियो प्रस्तुति के साथ, बी.ए.पी.एस. के वरिष्ठ संतों द्वारा उनके दिव्य जीवन, गुणों और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणादायी उद्बोधन दिए गए। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल तथा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का बी.ए.पी.एस. के वरिष्ठ संतों द्वारा स्वागत किया गया। इस महोत्सव के दौरान इंग्लैंड से पधारे गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी द्वारा परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 'हिन्दू ग्रंथ के सबसे विराट सामूहिक पाठ' के लिए यह रिकॉर्ड परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को प्रदान किया गया। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से बी.ए.पी.एस. संस्था के 3 से 13 वर्ष की आयु के 15,000 से अधिक बच्चों ने सत्संगदीक्षा ग्रंथ का एक वर्ष में संस्कृत में पूर्ण मुखपाठ किया।परम पूज्य महंत स्वामी महाराज द्वारा रचित 315 श्लोकों से युक्त सत्संगदीक्षा ग्रंथ आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।यह एक ऐतिहासिक और विरल उपलब्धि है कि किसी एक संस्कृत ग्रंथ का, उसके रचयिता की प्रत्यक्ष उपस्थिति में, 15,666 बालक-बालिकाओं द्वारा मात्र एक वर्ष में संपूर्ण ग्रंथ — अर्थात 315 श्लोकों — का सामूहिक मुखपाठ और गायन किया गया हो।

भूलकर भी किसी को मत बताना ये 6 बातें!

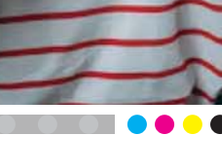

बढ़-चढ़कर बताते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कहां-कहां से कितना पैसा आ रहा है। ये सब आपके जीवन में लोगों की बुरी नजर अट्रैक्ट करता है।

5 अपनी खुशियां

सोशल मीडिया पर हर कोई आजकल अपने स्पेशल मूमेंट्स साझा करने में लगा हुआ रहता है। कुछ हद तक ये ठीक है लेकिन लोगों के साथ हर स्पेशल मूमेंट शेयर करने से बचें। कुछ खुशियां आपकी पर्सनल होती हैं, जिन्हें हर किसी के साथ शेयर करना ठीक नहीं है। लोगों की जलन और नेगेटिविटी को फालतू में भला अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करना।

6 अपने ट्रैवल प्लान

कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे तो वो देख ही लेंगे। बहुत से लोग यही करते हैं, फिर कहीं जा ही नहीं पाते। जब आप पहले ही बखान कर देते हैं, तो लोगों के दस ओपिनियन सुनते हैं, जजमेंट सुनते हैं और जेलेसी भी अट्रैक्ट करते हैं।

4 अपनी इनकम और उसके सोर्स

हर किसी के सामने अपनी इनकम के बारे में बताने से भी परहेज करें। कई लोग प्लान खुद तक सीमित रखें और उनपर काम करें। जब वो हो जाएंगे तो लोग खुद-ब-खुद देख ही लेंगे।

करने से बचना चाहिए। ऐसा कर के आप जाने-अनजाने लोगों की नेगेटिविटी, जलन की भावना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किसी चीज की तैयारी भी कर रहे हैं, तो पहले से ढिंढोरा ना पीटें। मेहनत में लगे रहें, काम जब होगा तब दुनिया खुद जान जाएगी।

अपनी लव लाइफ

जब आप अपनी हर बात लोगों से शेयर कर देते हैं, तो जाहिर है लोगों के मन में जलन और नेगेटिविटी की भावना पैदा होती है। ऐसे में कई बार इविल आई यानी बुरी नजर लगने की वजह से आपका काम ही ठप हो जाता है।

अपनी लव लाइफ को जितना प्राइवेट हो सके रखना चाहिए। आजकल लोग रिलेशनशिप शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट होता है, कुछ दिनों बाद ही ब्रेकअप। इसलिए बेहतर है कि उसे प्राइवेट रखें, जब तक वो परमानेंट ना हो जाए।

3 अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटजी

आप अपने करियर, लाइफ या किसी भी जरूरी चीज में आगे क्या प्लान कर रहे हैं, ये भी हर किसी से बताना जरूरी नहीं है। ऐसा करने से भी आप लोगों की जजमेंट और बुरी नजर के शिकार बन सकते हैं। अपने

1 हमेशा प्राइवेट रखें ये बातें

हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है, जो हम दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। खासतौर से जिन्हें हम अपना समझते हैं। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपका काम सिर्फ बातों तक ही रह जाता है, वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता। इसके पीछे एक वजह है लोगों की बुरी नजर लगना। जब आप अपनी हर बात लोगों से शेयर कर देते हैं, तो जाहिर है लोगों के मन में जलन और नेगेटिविटी की भावना पैदा होती है। ऐसे में कई बार इविल आई यानी बुरी नजर लगने की वजह से आपका काम ही ठप हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से बातें हैं, जो आपको लोगों से बिल्कुल शेयर नहीं करनी हैं। खासतौर से जबतक वो पूरी ना हो जाएं।

2 अपनी सक्सेस को प्राइवेट रखें

अपनी सक्सेस के बारे में ज्यादा लोगों के आगे गुणगान

बहाल प्राचार्य की कुर्सी पर बवाल, शिक्षक दो खेमों में बंटे

बच्चों की पढ़ाई हाशिये पर, परीक्षा सिर पर और स्कूल में चल रही राजनीति

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल इन दिनों शिक्षा नहीं, बल्कि कुर्सी की जंग के कारण चर्चा में है। निलंबन के बाद बहाल हुई प्राचार्य वंदना पांडे के स्कूल लौटते ही शिक्षकों के बीच खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई है। एक पक्ष प्राचार्य के समर्थन में है, तो दूसरा खुला विरोध करता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ शिक्षक इस पूरे विवाद को तमाशे की तरह लेते भी दिखाई दे रहे हैं।

पूर्वाग्रह और आशंका से ग्रसित कुछ शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर प्राचार्य को हटाने की मांग करने लगे। जब इस संबंध में शिक्षकों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, तो एक शिक्षिका ने साफ कहा कि वह पूरे स्टाफ के साथ है, जबकि एक अन्य शिक्षक ने खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन सवालों के ठोस जवाब नहीं दे पाए।

जब स्कूल के बच्चों से सीधे बात की गई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। बच्चों ने बताया कि वंदना पांडे के वापस आने से वे खुश हैं। उनका कहना था कि

प्राचार्य की मौजूदगी में स्कूल में अनुशासन रहता है, कामकाज सुचारू रूप से चलता है और पढ़ाई का माहौल बना रहता है।

हालांकि, बातचीत के दौरान कुछ शिक्षक बार-बार वहां पहुंचते रहे, जिन्हें देखकर बच्चे सहम जाते और खुलकर बोलने से कतराते दिखे। पूरा मामला यह सवाल खड़ा करता है कि शिक्षक राजनीति के इस खेल में बच्चों का बौद्धिक और शैक्षणिक भविष्य आखिर किसके भरोसे है?

आरोप है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है, जबकि उनकी परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। यह समय छात्रों के लिए सबसे अहम है, जो उनके भविष्य की दिशा तय करता है।

इस पूरे विवाद पर प्राचार्य वंदना पांडे ने कहा कि मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ज्वाइन करते ही मैंने पूरे स्टाफ की बैठक ली और साफ कहा कि परीक्षा नजदीक है। सभी शिक्षक बच्चों के हित में ईमानदारी से काम करें, ताकि परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत हो।

क्या कहता है नियम?

स्वतंत्रता पूर्व लागू फंडामेंटल रूल 1921 के नियम 14 के अनुसार कर्मचारी संहिता में निलंबन और धारणाधिकार को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं। धारणाधिकार का अर्थ है ङ्क किसी सरकारी कर्मचारी का उस स्थायी पद पर अधिकार, जिस पर उसकी नियमित नियुक्ति है।

निलंबन की स्थिति में भी कर्मचारी का धारणाधिकार समाप्त नहीं होता, क्योंकि निलंबन कोई दंड नहीं, बल्कि अस्थायी प्रशासनिक कार्रवाई है। निलंबन के बाद बहाली होने पर कर्मचारी का अपने मूल पद पर अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

आत्मानंद स्कूल में चल रही यह लड़ाई किसी एक कुर्सी की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की सोच पर सवाल है।

अगर शिक्षक आपसी राजनीति में उलझे रहे, तो इसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जिनके भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है।

साइबर जागरूकता और ट्रैफिक सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया

बिर्रा पुलिस द्वारा साप्ताहिक बाजार में की गई जागरूकता अभियान

बिर्रा //समय दर्शन। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय ङ्क्क के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत थाना प्रभारी बिर्रा निरीक्षक जय कुमार साहू द्वारा आज दिनांक 05 फरवरी दिन गुरुवार को बिर्रा पुलिस एवं ग्राम कोटवार द्वारा बिर्रा के साप्ताहिक आम बाजार में नागरिकों को साइबर जागरूकता और यातायात सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में बाजार में आने वाले आम जनता को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। बिर्रा थाना प्रभारी निरीक्षक जय कुमार साहू ने लोगों को बताया कि साइबर अपराध जैसे फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड और ऑनलाइन लेन-देन में सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के महत्व पर भी निरीक्षक जयकुमार साहू के द्वारा प्रकाश डाला गया। ग्राम कोटवार एवं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लोगों से व्यक्तिगत अनुभव साझा कर उन्हें सजग रहने के लिए प्रेरित किया।थाना प्रभारी बिर्रा निरीक्षक जयकुमार साहू ने आगे बताया कि इस प्रकार के अभियान का उद्देश्य न केवल जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि लोगों को तकनीकी और डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखना भी ज्यादा जरूरी है। नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि वे अब अधिक सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपना कर अपने व अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने का कष्ट करेंगे।

इस अवसर पर थाना प्रभारी बिर्रा निरीक्षक जयकुमार साहू, प्रधान आरक्षक विवेक सिंह एवं पुलिस के जवान और कोटवार के अलावा पंचायत पदाधिकारी के साथ ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 की तैयारियां तेज

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

जांजगीर-चांपा / जिले में 11, 12 एवं 13 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज शासकीय हाई स्कूल मैदान जांजगीर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ऐतिहासिक विष्णु मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए मंदिर परिसर में आकर्षक लाइटिंग एवं साज-सज्जा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान महोत्सव स्थल में विभिन्न विभागों एवं निजी संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉल किसानों की आवश्यकता एवं हित को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएं। उन्होंने कृषि आधारित योजनाओं, आधुनिक तकनीकों, बीज, उर्वरक, जैविक खेती, पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने कहा। साथ ही किसानों को नई कृषि तकनीक, आधुनिक उपकरण, ड्रोन तकनीक सिंचाई के नवाचार एवं उन्नत बीजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मंच, स्टॉल व्यवस्था, साउंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्किंग, यातायात व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वनमंडलाधिकारी श्री हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

लोरमी तहसीलदार की कार्यशैली से नाराज़ पटवारी लोरमी में राजस्व कार्य ठप

अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्व पटवारी संघ मुंगेली ने जिला प्रशासन को स्मरण करते हुए तीन दिन में समाधान नहीं हुआ तो जिलेभर में हड़ताल की चेतावनी

मुंगेली (समय दर्शन) लोरमी तहसील लोरमी में कार्यरत पटवारी, तहसीलदार शेखर पटेल की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर दिनांक 29 जनवरी 2026 से तहसील लोरमी के सभी राजस्व निरीक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से तहसील कार्यालय का संपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो गया है, जिससे आम नागरिकों को नामांतरण, सीमांकन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी जैसे आवश्यक कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पटवारियों का कहना है। कि तहसील स्तर पर लंबे समय से प्रशासनिक अव्यवस्था एवं कार्य संचालन में कठिनाइयों के चलते वे मानसिक दबाव में कार्य कर रहे थे। कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, जिससे बाध्य होकर उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।

इस मामले में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी में कार्यरत अधिकारी प्रशासन द्वारा 30 जनवरी एवं 2 फरवरी 2026 को चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई एवं ज्ञापन सौंपा गया लेकिन दोनों बैठकों में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। पटवारी संघ का कहना है कि बातचीत केवल औपचारिक रही, जबकि जमीनी समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। राजस्व पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पटवारियों की समस्याओं का तीन दिवस के भीतर निराकरण किया जाए। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होता है, तो दिनांक 9 फरवरी 2026 से जिले के समस्त पटवारी तहसील लोरमी के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि आंदोलन और व्यापक हुआ, तो जिले की पूरी राजस्व व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।, जिसकी सीधी मार आम जनता पर पड़ेगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से शीघ्र हस्तक्षेप कर प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है।फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर चर्चा जारी है,। वहीं आम नागरिक राजस्व कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

ए एम/एन एस इंडिया बनी भारत की पहली एकीकृत इस्पात कंपनी, जिसे इस्पात मंत्रालय की नई ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के तहत ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन मिला

एस एच अज़हर/दंतेवाडा । किरंदुल आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने इस्पात मंत्रालय की नई ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के तहत ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली देश की पहली एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। कंपनी के हॉट रोल्ड (HR) कॉयल्स और शीट्स को 4-स्टार रेटिंग, जबकि कोल्ड रोल्ड (CR) कॉयल्स और शीट्स को 3-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।

ये प्रमाणित ग्रीन स्टील उत्पाद ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, जिससे ग्राहक अपनी वैल्यू चेन में स्कोप-3 उत्सर्जन कम कर सकेंगे।

AM/NS INDIA

सर्टिफिकेशन के लिए उत्सर्जन तीव्रता 2.2 tCO2e/tfs से कम होनी आवश्यक है, और NISST द्वारा कठोर ऑडिट के बाद यह मान्यता मिली।

AM/NS India ने प्राकृतिक गैस आधारित DRI प्रक्रिया (65% क्षमता), नवीकरणीय ऊर्जा निवेश (1 त्नङ्ख हाइब्रिड प्रोजेक्ट सहित) और आगामी 2 GW+ क्षमता विस्तार से 2015 के बाद 35त्न+ उत्सर्जन तीव्रता में कमी हासिल की है। स्नङ्घ 2025 में राष्ट्रीय औसत से 14त्न कम उत्सर्जन दर्ज किया गया। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 20% और कमी करना है।

CEO दिलीप ऊम्मेन ने कहा कि यह मान्यता कंपनी की लो-कार्बन प्रक्रियाओं और स्वच्छ ऊर्जा निवेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत के डी-कार्बनाइजेशन लक्ष्यों और 'स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स' विजन से जुड़ी है।

यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी इस्पात उत्पादक के रूप में मजबूत बनाती है।

ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद सम्पन्न

तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद में दौड़,खो - खो ,कबड्डी, जलेबी दौड़, क्रिकेट, गुब्बारा फोड़, सुई - धागा ,लंगड़ी दौड़ , कुर्सी दौड़ ,बैडमिंटन इत्यादि खेलों का सफल आयोजन किया गया

जांजगीर /समय दर्शन // ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर में तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना रहा। खेलकूद का आयोजन विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेश यादव के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ, जिनके नेतृत्व में सभी खेल प्रतियोगिताएँ अनुशासित एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित की गईं।

तीन दिवसीय आयोजन के अवसर पर माँ सरस्वती के छाया चित्र पर पूजन - अर्चन कर खेलकूद का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं कार्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहे तथा विद्या, विनय, विवेक एवं सद्बुद्धि की कामना की गई।

इस तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद महोत्सव में नर्सरी से लेकर कक्षा बारहवीं तक के हिंदी एवं अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से सहभागिता रही। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे यह आयोजन समावेशी, उत्साहपूर्ण एवं अनुशासित रूप में संपन्न हुआ। छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों तक सभी में खेलों के प्रति विशेष उत्साह

देखने को मिला।

खेलकूद प्रतियोगिताओं में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न खेलों के साथ-साथ नर्सरी एवं छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से गुब्बारा गेम,जलेबी दौड़ ,गुब्बारा फोड़,सुई - धागा का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे-मुन्ने बच्चों ने पूरे उल्लास एवं आनंद के साथ भाग लिया। इसके अतिरिक्त दौड़, कबड्डी, खो-खो, लंबी कूद, ऊँची कूद, लंगड़ी दौड़, बैडमिंटन, साइकिल रेस सहित अनेक खेलों में विद्यार्थियों ने अनुशासन एवं खेल भावना का परिचय देते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का भी विशेष आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं की टीमों ने भाग लिया और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। क्रिकेट मैचों के दौरान विद्यार्थियों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता एवं अनुशासन देखने को मिला। रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया और खेल मैदान तालियों से गूंज उठा।

खेलों के दौरान शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया गया, जिससे विद्यार्थियों का उत्साह पूरे आयोजन के दौरान बना रहा। सभी कक्षाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस खेल महोत्सव को सफल एवं स्मरणीय बना दिया।

वार्षिक खेलकूद के अंतिम दिन विद्यार्थियों के साथ-साथ सभी शिक्षकगण एवं विद्यालय स्टाफ ने भी विभिन्न खेलों में भाग लिया। शिक्षकों एवं स्टाफ की सहभागिता से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा तथा विद्यालय में आपसी सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। समापन दिवस पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के निर्धारित स्थानों के समक्ष खेलों का प्रदर्शन कर तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत समापन किया गया। इस अवसर पर खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई तथा आयोजन को सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों, आयोजकों एवं आयोजन समिति को हार्दिक बधाई दी गई।

संक्षिप्त समाचार

अमेज़न और IIT रुड़की ने कृषि अवशेष से इनोवेटिव पैकेजिंग समाधान विकसित करने के लिए की साझेदारी

रायपुर: अमेज़न इंडिया ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत कृषि अवशेषों से ऐसे नए पैकेजिंग मटीरियल विकसित किए जाएंगे, जो पारंपरिक लकड़ी आधारित कागज़ और प्लास्टिक पैकेजिंग का टिकाऊ विकल्प बन सकें। इस परियोजना का उद्देश्य गैर-लकड़ी आधारित कागज़ तकनीक विकसित करना है, जिससे कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उपयोग में लाया जा सके और वर्जिन वुड पल्प पर निर्भरता कम हो। प्रस्तावित पैकेजिंग हल्की होने के साथ-साथ मज़बूत होगी, पूरी तरह रीसाइकल करने और घरेलू स्तर पर कंपोस्ट किए जाने योग्य होगी। अमेज़न इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस) अभिनव सिंह ने कहा, अमेज़न में हम भारत का सबसे तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद ऑपरेशंस नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और इसे अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। IIT रुड़की के साथ यह साझेदारी हमें कृषि अवशेषों से इनोवेटिव पैकेजिंग विकसित करने का अवसर देती है। भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पन्न होता है। यदि इसे पैकेजिंग में बदला जाए, तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं और पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता घटा सकते हैं। IIT रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा, आज सस्टेनेबिलिटी कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। अमेज़न और IIT रुड़की का यह सहयोग सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में भारत के विज़न को आगे बढ़ाने का एक ठोस कदम है, जो स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति जैसे सरकारी अभियानों के अनुरूप है। कृषि अवशेषों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदलकर हम पराली जलाने और वर्जिन मटीरियल पर निर्भरता जैसी दो बड़ी चुनौतियों से एक साथ निपट रहे हैं। यह पहल दिखाती है कि अकादमिक शोध और उद्योग की साझेदारी मिलकर देश के लिए टिकाऊ और आत्मनिर्भर समाधान कैसे तैयार कर सकती है।

2026 की कोमेड-के और यूनि-गॉज की प्रवेश परीक्षा 09 मई को होगी आयोजित

रायपुर: कोमेड-के यू-जी-ई-टी / यूनी-गॉज 2026 एंट्रेन्स एग्ज़ामिनेशन शनिवार, 09 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह एकीकृत नेशनल-लेवल टेस्ट पूरे भारत में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसके माध्यम से कर्नाटक के 150+ इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ और देशभर के 30+ रेप्यूटेड प्राइवेट, सेल्फ-फंडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बी.ई./बी.टेक प्रोग्राम्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये प्रोग्राम्स कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ एसोसिएशन (कूपेका) से संबद्ध संस्थानों और यूनी-गॉज मेंबर यूनिवर्सिटीज़ द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। यह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट पूरे भारत के 200+ शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 400+ टेस्ट सेंटर्स शामिल होंगे। लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। देशभर के सभी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं।

स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौ महीनों के वित्त परिणाम घोषित किए

नईदिल्ली। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड था, ने अपने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौ महीने के परिणाम घोषित किए, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, फाइनेंसियल ग्रोथ और लांग टर्म वैल्यू क्रिएशन को दर्शाता है।

मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव कंदुला ने कहा: वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौवीं माही हमारी कंपनी के लिए एक निर्णायक दौर है। हमने सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में खुद को परिवर्तित कर लिया है, साथ ही अपने मुख्य ग्लास-लाइनिंग बिज़नेस को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लास-लाइन्ड टेक्नोलॉजीज़ में नेतृत्व, कंडक्टिविटी ग्लास-लाइन्ड रिएक्टरों जैसे ब्रेकथ्रू इनिवेशंस, शेल-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स में मजबूत पकड़ और विस्तारित टर्नकी इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड लॉंगटर्म, सस्टेनेबल मूल्य क्रिएशन के लिए अच्छी स्थिति में है। हमारा ध्यान एक्सक्यूशन एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और अपने शेयरधारकों के लिए निरंतर मूल्य क्रिएशन पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण तिमाही है। इस तिमाही के दौरान, कंपनी औपचारिक रूप से अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया।

खबर-खास

भूमि अधिग्रहण में हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रभावित किसानों ने राजीव भवन दुर्ग में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर से की भेंट

दुर्ग। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के साथ हो रहे गंभीर अन्याय, मुआवजा निर्धारण में मनमानी, सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) की अनदेखी, प्रशासनिक दबाव एवं आजीविका छिनने के विरोध में प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राजीव भवन दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर से भेंट-मुलाकात की। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल मुआवजा उनकी आजीविका का विकल्प नहीं है, इसलिए भूमि के बदले स्थायी नौकरी/रोज़गार की व्यवस्था की जाए।

दुर्ग जिले अंतर्गत ग्राम परुई, पाऊवारा, चंगोरी, बिरेझर, थनौद, कोनारी, चंदखुरी, भानपूरी, बोरीगारका, करगाडीह, खोपली, घुघसीडीह, कोकड़ी, कोडिया सहित अन्य ग्रामों के किसानों ने बताया कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन भूमि का मूल्यांकन न तो बाजार दर के अनुसार किया जा रहा है और न ही वर्तमान गाइडलाइन का पालन हो रहा है। ग्राम सभा की सहमति के बिना जबरन अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे किसान भय और असमंजस की स्थिति में हैं।

किसानों ने कहा कि एकमुश्त 5 लाख या सीमित मुआवजा राशि आजीविका का स्थायी विकल्प नहीं हो सकती। भूमि चले जाने के बाद किसान और उसके परिवार के सामने रोज़गार, शिक्षा और भविष्य की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रभावित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना में स्थायी नौकरी अथवा समकक्ष रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया जाए। किसानों ने यह भी मांग रखी कि जब तक भूमि के बदले नौकरी की स्पष्ट नीति लागू नहीं होती, तब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि भूमि के साथ-साथ मकान, कुआँ, बोर, पेड़-पौधे, बाड़ी, सिंचाई एवं विद्युत संरचनाओं का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिससे प्रभावित परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं। कई स्थानों पर सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) केवल कागज़ी खानापूर्ति बनकर रह गया है, जबकि कानून के अनुसार ग्राम सभा की वास्तविक सहभागिता और पूर्व सहमति अनिवार्य है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनकर उन्हें बेरोज़गार बना रही है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 केवल मुआवजे की बात नहीं करता, बल्कि पुनर्वास, पुनर्स्थापन और आजीविका की सुरक्षा को भी अनिवार्य बनाता है, जिसे भाजपा सरकार लगातार कुचल रही है।

श्री ठाकुर ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि भूमि के बदले प्रभावित परिवारों को स्थायी नौकरी दी जाए, ताकि किसान सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें। केवल पैसे देकर किसानों की जमीन लेना अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने भूमि के बदले नौकरी, उचित मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी प्रभावित किसानों के साथ मिलकर सड़क से सदन तक व्यापक और आक्रामक आंदोलन करेगी।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी किसानों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पूरी ताकत से संघर्ष करेगी और किसी भी कीमत पर किसानों के अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

भेंट-मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, भूमि के बदले स्थायी नौकरी सुनिश्चित की जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

उक्त संबंध में 13 फरवरी को किसानों द्वारा हिंदी भवन के सामने, झाड़ूराम देवांगन स्कूल यात्री प्रतीक्षालय के समीप एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर दुर्ग को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इस दौरान देवेंद्र देशमुख, प्रभावित किसान अमित साहू, लक्ष्मी मानिकपुरी, शकुन साहू, लक्ष्मण निषाद, लखन निषाद, व्यासनारायण साहू, धनेश राम साहू, भंवर लाल देशमुख, यशवंत देशमुख, सतीश देशमुख, मेहतरू साहू, बिहारी लाल, अजय कुमार सिन्हा, विष्णु चंद्राकर, चैन सिंह साहू, प्रेम लाल साहू, कल्याण पटेल, यशवंत साहू, बिसेसर साहू, धनऊ कोसरे, मोहन चंद्राकर, मलेश निषाद, चेतन भारद्वाज, रामाधार, पुकेश्वर यादव, रामचरण भारद्वाज, बुधारू, दिलीप देशमुख, मुकेश देशमुख, गोवर्धन देशमुख, प्रदीप देशमुख, उमेश साहू, महेश देशमुख, मोहन हरमुख, बीरेंद्र देशमुख सहित सैकड़ों प्रभावित किसान उपस्थित रहे।

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

नेताओ और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकल कर नारे बाजी की ओर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दंतेवाड़ा(05-02-2026)केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम में परिवर्तन और नए नियमों को लागू करने के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने हुंकार भरी।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष सलीम रजा उस्मानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाली और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र के फैसलों को जनविरोधी करार दिया। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता (दुर्गा मंडप, आंवराभाटा) में एकत्रित हुए, जहां आम सभा कर सरकार के खिलाफ जमकर भाजपा की नितियों का विरोध किया।सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सलीम रजा उस्मानी ने कहा कि योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल इसकी मूल भावना को कमजोर करना है, बल्कि राष्ट्रपिता की ऐतिहासिक विरासत का अपमान भी है।यह योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार है, लेकिन नए बदलावों से ग्रामीणों के हितों पर चोट की जा रही है। पीसीसी सयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा ने कहा सरकार महात्मा गांधी के नाम से डरती है, इसलिए योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को तोड़-मरोड़ना चाहती है। मनरेगा करोड़ों गरीब मजदूरों के लिए जीवनरेखा है। इसका नाम बदलना केवल एक शब्द परिवर्तन नहीं,

बल्कि गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला और संविधान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। सरकार पहले रोजगार खत्म करती है, फिर रोजगार की गारंटी देने वाली योजना का नाम बदलकर अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रही है। यह लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं, संविधान, लोकतंत्र और गांधीवादी मूल्यों को बचाने की लड़ाई है।

तूलिका कर्मा ने कहा ने कहा मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक योजना का नाम बदलना नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी के विचारों, संघर्ष और गरीबों के हक को मिटाने की साजिश है। भाजपा सरकार इतिहास बदलकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस गांधी-विरोधी फैसले को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। मनरेगा से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है और यह योजना उनकी आर्थिक रीढ़ है। इसके साथ छेड़छाड़ करना सीधे तौर पर ग्रामीण भारत पर हमला है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सभा को जनपद उपाध्यक्ष भीमसेन मंडावी, आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष कोपाराम ,महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कर्मा ने सम्भोधित कर अपने विचार रखे । धरना पश्चात दुर्गा मण्डप से रैली के रूप में जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों से सम्बंधित तख्तियां, झंडे व बैनर लेकर प्रदर्शन किया ।इसी बीच बैरिकेड पार करने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के मध्य झूमा झटकी भी हुई।

इस दौरान पूर्व विधायक देवती कर्मा, वीरेंद्र गुप्ता, सुलोचना कर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कर्मा, राजेन्द्र कौर ,सुमित्रा शोरी, रामकुमार नाग, राजेन्द्र कुमार, नंदा राम कुंजाम, सुखराम नाग, कीरत अलामी, दीपक कर्मा,गणेश दुर्गा, रवीश सुराना, बबलू सिद्दीकी, शंकर कुंजाम, आकाश विस्वास,रितेश जैन,उमेश कश्यप, सोहन भवानी, राकेश कर्मा, पंकज बनिक, महेश मौर्या, मंगल मौर्या, केशव इच्छम, मनोज साहा, सुनीता कर्मा,जितेंद्र कश्यप,संजय विश्वकर्मा, महेश कर्मा, शिवराम मंडावी, सुशीला नियाल, ब्रम्हा सोनानी, उस्मान खान,अशोक बैरागी, मुन्ना राम वेक, सोमाली, सुरेश कड़ती, राजेश वेट्टी, वीरेंद्र नाग,सोहन यादव,सत्यनारायण नाग,ऋषभ सुराना, भीमसेन कड़ती, बलदेव शोरी, पूनम चौहान, अविनाश सरकार, विक्रम सोनवानी, विजय भोगामी, सुनील गाइन, सलमान नवाब, सुनील जोशी, गायेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला ,पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे।

बिलासपुर पुलिस रेंज में पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग की परिकल्पना से अनुभव क्यू आर कोड किया गया प्रारम्भ

संभाग आयुक्त ,पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया अनुभव क्यू आर कोड लॉन्च

थाने की व्यवस्था के संबंध में आमजन दे सकेंगे सीधे पुलिस महानिरीक्षक को फीडबैक

रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक भी वर्चुअली हुए शामिल

सारँगढ़ बिलाईगढ़ -आज दिनांक 5/2/27 का दिन, बिलासपुर रेंज की पुलिस के लिए एक नवाचार के शुभारंभ का साक्षी बना।आज बिलासपुर पुलिस लाइन के चेतना हाल में संभाग आयुक्त श्री अनिल जैन, पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग, जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं छद्वत्न तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह की प्रत्यक्ष एवं रेंज के जिलों, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली,जी पी एम ,सारंगढ़ एवं सक्ती के पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअली उपस्थिति के दौरान, अनुभव क्यू आर कोड का शुभारंभ किया गया।

इस क्यू आर कोड को स्कैन करके आम जन थाने से, संबंधित अपना फीडबैक दे सकेंगे।

इस अवसर पर आईजीपी श्री रामगोपाल गर्ग ने,जो इस ऐप के प्रणेता भी हैं, ने अपने उद्बोधन में बताया, की अब समय आ गया है कि पुलिस तकनीकी रूप से सक्षम बने, और आम जन भी, सरल तकनीक के माध्यम से पुलिस के साथ अपने अनुभव साझा कर सके। इसके लिए ये पहल अनुभव के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें थाने, और पुलिस के अन्य कार्यालयों में क्यू आर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें अपने मोबाइल से स्कैन करके कोई भी व्यक्ति अपना फीडबैक दे सकता है।कोड को स्कैन करने पर एक सरल गूगल फॉर्म खुलता है, जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से, संबंधित व्यक्ति अपना फीडबैक दे सकता है,जो सबमिट करने पर सीधे पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में दर्ज हो जाएगा।फीडबैक देने एला व्यक्ति चाहे तो अपनी पहचान और मोबाइल नंबर भी गोपनीय रख सकता है, इसे पूरी तरह से वैकल्पिक रखा गया है। आईजीपी श्री गर्ग ने आगे बताया कि,आज से रेंज के सभी आठ जिलों में एक साथ इस ' अनुभव' सिस्टम का आरम्भ किया जा रहा है,इसके लिए रेंज के सभी थानों में क्यू आर कोड की स्थापना कर दी गई है।इस अवसर पर जिला बिलासपुर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा , ये पुलिस प्रशासन की ऐसी पहल है, जिससे आम जन, अपना अनुभव और समस्याएं बिना किसी वरिष्ठ कार्यालय के चक्कर काटे ,सीधे बता सकते हैं,और अपनी बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।संभागायुक्त श्री अनिल जैन जी ने कहा, की नवाचार को अपनाना वर्तमान समय की मांग है, और हम अपने कार्य के लिए स्वयं पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, हम जनता के सेवक हैं, इसलिए हमारे काम का पर्यवेक्षण भी आमजन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया, की बिलासपुर जिले के सभी थानों में 'अनुभव के लिए क्यू आर कोड लगा दिए गए हैं, और अब आम जन, अपना फीडबैक इसे स्कैन करके सीधे दे सकते हैं।उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक की इस पहल को सार्थक बताते हुए कहा, की अब इससे थाने आने वाले फरियादियों को जो भी अनुभव थाने से मिलेगा, उससे प्राप्त फीडबैक के आधार पर जो भी व्यवस्था में सुधार किए जाने हैं वो किए जाएंगे।कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशिमोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी ने भी अपने विचार रखे जिसमें उन्होंने इस ' अनुभव ' को एक सार्थक पहल बताते हुए, इससे पुलिसिंग को और बेहतर बनाने तथा थाने में रियल टाइम में फरियादियों को आने वाली समस्याओं को जानकर, उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी, ऐसा अपने संबोधन में बताया। कार्यक्रम गरिमामय रहा, जिसके दौरान सभी अतिथियों के द्वारा 'अनुभव 'का विधिवत शुभारंभ क्यू आर कोड का रिबन खोलकर किया गया।इस दौरान इससे संबंधित एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें 'अनुभव ' के उपयोग और उपयोगिता के संबंध में जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकजन, समाज सेवी संस्थाओं के माननीय लोग, प्रिंट तथा सोशल मीडिया के प्रमुख प्रबुद्धगण की गरिमामय उपस्थिति रही।आज से ही यह व्यवस्था रेंज के सभी जिलों के सभी थानों में प्रारम्भ कर दी गई है। आईजीपी श्री रामगोपाल गर्ग ने आम जनो से अपील की है, की इसका सदुपयोग करें, और अपने सही,वास्तविक तथा महत्वपूर्ण फीडबैक को देकर, व्यवस्था में सुधार के सहभागी बने। यदि कुछ अच्छा हो तो उसे भी शेयर किया जाए, और जो कमी आपको महसूस हो, उसे भी निर्भय होकर बताएं। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के द्वारा सभी अतिथियों को स्मरण चिन्ह प्रदान किए गए।इस गरिमामय कार्यक्रम के साथ आज से बिलासपुर रेंज में जनता से प्रत्यक्ष संवाद के तहत ' अनुभव ' के माध्यम से क्यू आर कोड स्कैन कर फीडबैक लेने की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।

विद्युत विभाग में सम्पन्न हुआ रजत जयंती

गरियाबंद (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2026 के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड संभागीय कार्यालय एवम उपसंभाग गरियाबन्द द्वारा 5 फरवरी गुरुवार को विधुत विभाग के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया।उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिखीराम यादव अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अध्यक्षता सोहन ध्रुव अध्यक्ष जनपद पंचायत गरियाबंद विशिष्ट अतिथि आसिफ मेमन,उपाध्यक्ष नगर पालिका गरियाबंद,लेखराम साहू,उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गरियाबंद,बबिता सेन,सभापति व जनपद सदस्य गरियाबंद,भागीरथी मांझी,पार्षदगण सुरेन्द्र सोनटके,रेणुका साहू,विष्णु मरकाम,सूरज सिन्हा, बिंदु सिन्हा,खेमसिंग बघेल,छगन यादव,पूर्व पार्षद प्रतिभा पटेल रहे।कार्यक्रम में सरपंच सढौली लक्ष्मी ठाकुर,उपभोक्तागण,नागरिकगण,हितग्राही,विधुत विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम की शुरुवात छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चना एवम अरपा पैरी के धार राजकीय गीत से छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना से की गई। सर्वप्रथम विधुत विभाग के 25 वर्ष के सफर और विकास और योजनाओं के संबंध कार्यपालन अभियंता श्री हेमंत ठाकुर द्वारा बताया गया। इसके बाद केंद्र और राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्रहियों को प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि एवम अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद लगातार दो वर्षों से नियमित बिजली बिल का भुगतान करने वाले सम्मानीय उपभोक्तओं को प्रमाण पत्र वितरित किये गए।कार्यक्रम को रिखीराम यादव,सोहन ध्रुव,आसिफमेमन,लेखराम साहू एवम सुरेन्द्र सोनटके ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि रिखीराम राम यादव ने बताया कि गरियाबंद और गरियाबंद क्षेत्र में विगत 25 वर्षों में विधुत क्षेत्र में काफी विकास हुवा है। छत्तीसगढ़ ने भी अपने रजत वर्षों के सफर में काफी उपलब्धि हासिल की है। लोगों के हित के सभी सुविधाएं बिजली के बिना अधूरी हैं। श्री सोहन ध्रुव ने गरियबन्द विधुत विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे सेवा और कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यपालन अभियंता हेमंत ठाकुर,सहायक अभियंता गणेश प्रसाद और कनिष्ट अभियंता लक्की देवांगन द्वारा वर्तमान में सुविधा और निर्बाध विधुत प्रवाह की व्यवस्था की तारीफ की।लेखराम साहू ने भौतिक जीवन मे विधुत के बिना किसी भी चीज की कल्पना करना संभव नही है।उक्त कार्यक्रम अधीक्षण अभियंता वाय. के. मनहर के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिएअतिथियों ने विधुत विभाग और कुशल मंच संचालन के लिए भोगेंद्र सिन्हा की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में रेखा ठाकुर,राहुल दुर्गम, कैलाश साहू,अजय वर्मा,शिव वर्मा,भानसिंग कँवर,भोगेंद्र सिन्हा,ओमप्रकाश यदु,खिलावन साहू,रामसिंग पटिये,भोगेन्द्र साहू,गोकुल साहू, पन्चुराम यादव,विजय सिन्हा,बिहारी ध्रुव,पुष्पेंद्र साहू व समस्त तकनीकी और कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

आरंग की सड़कों पर विकास की रफ्तार: मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल से 2155 .97 लाख की बड़ी मंजूरी

आरंग/रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास अब घोषणा नहीं, ज़मीनी सच्चाई बनता जा रहा है। क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सड़क विकास की बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की सतत पहल और प्रभावी समन्वय का परिणाम है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिला रायपुर के गोढ़ीङ्कतोड़गांवङ्कबड़गांव मार्ग के 9.00 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए ?2155.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में सड़क निर्माण के साथ-साथ पुल-पुलिया का निर्माण भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय यातायात को स्थायी समाधान मिलेगा। इस सड़क के उन्नयन से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। किसानों को मंडियों तक पहुंच, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक सुविधा और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह योजना आरंग विधानसभा के आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी साबित होगी। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार विकास को प्राथमिकता नहीं, प्रतिबद्धता मानकर कार्य कर रही है। आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार मिल रही स्वीकृतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार विकास को काग़ज़ों से निकालकर ज़मीन पर उतार रही है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए जन प्रिय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव जी एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी आरंग विधानसभा को अधोसंरचना, सड़क, सिंचाई एवं जनसुविधाओं से जुड़ी अनेक नई सौगातें मिलती रहेंगी।

वीबी-जी-रामजी अधिनियम 2025: जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

ग्रामीण रोजगार, आजीविका संवर्धन व योजना क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधियों को दी गई विस्तृत जानकारी

मुंगेली (समय दर्शन) विकसित भारत-गारंटी फॅार रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी-रामजी) के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्हें सक्षम बनाना रहा। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्रीमती शांति देवचरण भास्कर, समस्त जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय सहित सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हुए।

कार्यशाला के दौरान विकसित भारत-गारंटी फॅार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिवस तक रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। कार्यशाला में जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, कृषि एवं पशुपालन आधारित कार्यों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु अनुमेय कार्यों की श्रेणियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम सभाओं की भूमिका को सशक्त बनाते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी कि वीबी-जी-रामजी योजना के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। योजना की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं डैशबोर्ड प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कार्यों की प्रगति पर सतत और प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के तहत जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र ग्रामीण परिवार इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित कर योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वीबी-जी-रामजी योजना का स्वागत करते हुए इसके सफल, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आपसी समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

संक्षिप्त-खबर

पाटन कालेज मे आरसेटी के सहयोग से स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

पाटन। शासकीय चंदूलाल चंद्राकार स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटन में प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा के मार्गदर्शन में आई क्यू एसी के तत्वाधान में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी दुर्ग के सहयोग से एकदिवासी स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा एवं मुख्य वक्ता गुलशन कुमार सिंह रिजनल मैनेजर थे। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा ने किया। उद्बोधन की कड़ी में प्राचार्य डॉक्टर नंदा गुरवारा ने मुख्य अतिथि बैंक ऑफबड़ौदा आरसेटी दुर्ग के मैनेजर एवं उसकी पूरी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में स्वरोजगार प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान करना है ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अगर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शासकीय सेवा में चयनित नहीं हो पाते हैं तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ़ आरसेटी दुर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बना सकते हैं। स्वरोजगार के प्राप्त कर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं। मुख्य वक्ता गुलशन कुमार सिंह मैनेजर ने संस्थान के इतिहास की जानकारी देते हुए कहा बताया कि यह संस्थान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रमाणित है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आयु 18 से 50 वर्ष तक निर्धारित है। जिसमें बीपीएल कार्डधारी, नरेगा कार्डधारी, स्वसहायता समूह के परिवार के सदस्य रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 50 से अधिक कार्यों का प्रशिक्षण जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मशरूम उत्पादन, अचार, पापड़ आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी कार्यों की प्रशिक्षण अवधि अलग-अलग है किसी का 10 दिन किसी का 30 दिन किसी का 45 दिन है। रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है प्रशिक्षण पूर्णता निशुल्क है। प्रशिक्षण उपरांत एक परीक्षा होती है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है साथ यहां प्रशिक्षित विद्यार्थियों को स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु बैंक द्वारा ऋण देने का भी प्रावधान अपने प्रमाण है। कार्यक्रम का संचालन आई क्यू ऐसी प्रमुख डॉ अरुणा साव एवं आभार डॉ आरके वर्मा विभागाध्यक्ष गणित ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, बडी संख्या मे छात्र छात्राये उपस्थित थे।

मंडल स्तरीय मां परमेश्वरी महोत्सव देवांगन समाज में शामिल हो रहे कल्पना नारद साहू सभापति जिला पंचायत दुर्ग

पाटन। - दक्षिण पाटन के रानीतराई में देवांगन समाज ने धूमधाम से मनाया मां परमेश्वरी जयंती!

इस कार्यक्रम के विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहे- कल्पना नारद साहू सभापति जिला पंचायत दुर्ग, श्री विजय देवांगन मंडल संरक्षक, सत्यनारायण टिकरिया सरपंच ग्राम पंचायत रानीतराई, नरेंद्र देवांगन, गजेंद्र देवांगन,सीताराम देवांगन, रामलाल देवांगन, संतोष साहू मंचासिन रहे!

कल्पना नारद साहू ने कहा की बसंत पंचमी के दिन देवांगन समाज अपनी इष्ट देवी को याद करते हैं इसी दिन को मां परमेश्वरी महोत्सव के रूप में मनाते हैं रानीतराई में मां परमेश्वरी जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया!

देवांगन समाज के पदाधिकारी दिलीप देवांगन, बिरेंद्र देवांगन, हितेश देवांगन,राधेश्याम देवांगन, धनुराम देवांगन, ठाकुरराम देवांगन,ओमप्रकाश देवांगन,राजेश देवांगन, लोमस, होमलाल, विजय,रामखिलावान, रामलाल,कुसुम देवांगन,अर्चना देवांगन,लीला देवांगन,कोमल धनेश्वर देवांगन सहित समस्त देवांगन समाज ग्रामवासी उपस्थित थे!

शासकीय प्राथमिक शाला बड़ेटेमरी में पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न

वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

बीईओ, बीआरसीसी के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम

बसना (समय दर्शन)। बसना विकास खण्ड अंतर्गत संकुल केन्द्र बड़ेटेमरी के शासकीय प्राथमिक शाला बड़ेटेमरी में सहायक शिक्षक श्रीमती नीलम कुमार द्वारा आंशिक रूप से नेवता भोज कराया गया द्य नेवता भोज में मिक्कर, बिस्किट, केला, मिठाई एवं सुस्वाद भोजन वितरित किया गया । सभी विद्यालयीन बच्चे सुस्वाद नेवता भोज ग्रहणकर आनंदित हुए । नेवता भोज पश्चात वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों ,विद्यालय के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोइया, स्वीपर और शिक्षादान करने वाली कु. इंदु पटेल, कु.पुष्पलता जगत को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बद्री विशाल जोल्हे, बसना विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक अनिल सिंह साव, सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लोकेश्वर सिंह कंवर के हाथों पुरष्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर सभी बच्चे खुश नजर आये। इस मौके पर एफएलएन नोडल शिक्षक शरण दास,बिलखंड के प्रधान पाठक विजय धृतलहरे, वरिष्ठ व्याख्याता शरद कुमार प्रधान,संकुल समन्वयक बड़ेटेमरी वारिश कुमार, भोलाप्रसाद सामल, चम्पतलाल चौधरी, मथामणी साहू,सहायक शिक्षक नीलम कुमार, कु. इंदु पटेल, कु. पुष्पलता जगत,स्वीपर सरिता साव,शासकीय प्राथमिक शाला बड़ेटेमरी के बच्चे उपस्थित थे। अंत में आभार प्रदर्शन संकुल समन्वयक वारिश कुमार द्वारा किया गया।

नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग के डायरेक्टर के 9 पदों का मतदान के जरिए होगा फैसला

बैंक के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में रुंगटा और परिवर्तन पैनल आमने-सामने, 14 फरवरी को होंगे मतदान

दुर्ग । नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के कुल 12 में से 9 संचालक मंडल सदस्य पद (डायरेक्टर) का चुनाव मतदान के जरिए होगा। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन यह चुनावी स्थिति स्पष्ट हुई। अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) के 6 पदों के लिए प्रत्याशी मंगल प्रकाश गुप्ता, पवन कुमार जैन, अंजय ताम्रकार, आमबर ताम्रकार, मनोज कुमार ताम्रकार, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, दिनेश कुमार मारोटी, अखिलेश मिश्रा,राजेश यादव, वेंकट सांई शास्त्री राव, कमल नारायण रुंगटा, संजय सिंह चुनाव मैदान पर है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित दो पदों के लिए प्रत्याशी सुनीता अग्रवाल, रजनी जोशी, संध्या तिवारी, नीलू देवांगन के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित एक पद पर पदम कुमार ताम्रकार और तेजबहादुर बंछोर के बीच आमने-सामने की टक्कर होगी। संचालक मंडल सदस्य (डायरेक्टर) के 9 पदों पर प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आबंटित कर दिए गए है। मतदान 14 फरवरी को श्री गुर्जर क्षत्रिय गुजराती समाज भवन मोतीपारा में होगा। मतदान के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। मतदान उपरांत इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के संचालक मंडल सदस्य (डायरेक्टर) पद के लिए हो रहे चुनाव में दो पैनल पहली बार आमने-सामने है। रुंगटा पैनल की कमान बैंक के पूर्व अध्यक्ष कमल नारायण रुंगटा संभाले हुए है, जबकि परिवर्तन पैनल का नेतृत्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव के जिम्मे में है। यह चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लिहाजा वे जीत के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते है। जिससे दोनो पैनलों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार-प्रसार में कूद पड़े है। जिसके चलते संचालक मंडल सदस्य (डायरेक्टर) पद के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के संचालक मंडल सदस्य (डायरेक्टर) पद के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव की गुरुवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। निर्धारित समय से पहले दो प्रत्याशी दीपक चावड़ा और रविशंकर भट्ट ने अपना नामांकन वापस ले लिया। चुनाव में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद निर्वाचन अधिकारी देवाशीष दास द्वारा निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। जिसके अनुसार सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउटेंट) के लिए आरक्षित दो पद के लिए श्रीपाल कोठारी और अरविंद चंद सुराना को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है,वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित एक पद पर श्रीमती वसुन्धरा चौरे निर्विरोध निर्वाचित हुई है। रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास ने बताया कि बैंक के निर्वाचन के अंतिम चरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसायटियों के प्रतिनिधियों व अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए 16 फरवरी को सूचना जारी की जाएगी। इन पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया 20 फरवरी को शाम 4 बजे से बैंक मुख्यालय अस्पताल वार्ड पचरीपारा में पूरी की जाएगी।

पीएम करेंगे महासमुंद की छात्रा सृष्टि साहू से परीक्षा पे चर्चा

महासमुन्द(समय दर्शन)। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत नौ वर्षों से निरंतर आयोजित किए जा रहे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इस वर्ष मुख्य आयोजन 6 फरवरी 2026 को प्रात: 10:00 बजे से किया जाएगा।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक लाइव, दूरदर्शन, पीएम ई-विद्या टीवी, रेडियो चैनलों एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम के लिंक प्राप्त होते ही विकासखंडों के माध्यम से सभी स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

विदित हो कि परीक्षा पे चर्चा के नौवें संस्करण में इस वर्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा की कक्षा 12वीं (गणित संकाय) की छात्रा सृष्टि का चयन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए किया गया है।

जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा रेखराज शर्मा द्वारा जिले के समस्त विकासखंडों के संबंधित अधिकारियों, प्राचार्यों एवं शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही विकासखंड स्तर पर सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी तनावमुक्त होकर सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में भाग ले सकें तथा अभिभावकों एवं शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

सिरपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सांसद रूपकुमारी चौधरी

महासमुंद(समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी सिरपुर में आयोजित तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन समारोह भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कला, संस्कृति और आस्था के इस महापर्व को ऐतिहासिक बताया।

सिरपुर महोत्सव में सांसद ने सिरपुर को विश्व विरासत स्थल बनाने पर दिया जोर।

सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि यह एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। प्राचीन विरासत से समृद्ध यह ऐतिहासिक नगरी आज विश्व विरासत स्थल बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है और अपनी सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से स्थापित कर रही है॥ उन्होंने कहा कि सिरपुर महोत्सव जैसे आयोजनों से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिलता है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। सिरपुर की ऐतिहासिक धरोहरें, बौद्ध विहार, मंदिर एवं प्राचीन स्थापत्य कला आज भी विश्व को भारत की समृद्ध संस्कृति का संदेश देती हैं। इस गरिमामयी अवसर पर महासमुंद विधायक योगेश्वर सिन्हा, बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री येतराम साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं पर्यटक भी समापन समारोह में शामिल हुए, जिनकी सहभागिता ने आयोजन को और अधिक भव्य और स्मरणीय बना दिया। समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकनृत्य, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक कला की झलक ने सिरपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति आज भी जीवंत, समृद्ध और विश्व को आकर्षित करने वाली है।

जोगी कांग्रेस नेता शमसूल आलम ने दुर्ग संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की मांग

राजनांदगांव। अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम ने आज दुर्ग संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। शमसूल आलम ने कहा कि इन जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बिना वैध दस्तावेजों और रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉटिंग का खेल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है और भूमि की कीमतों में अव्यवस्थित वृद्धि हो रही है। ज्ञापन में शमसूल आलम ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती, तो अजीत जोगी युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वे जल्द ही तीनों जिलों के कलेक्टर, रजिस्ट्रार, निगम कमिश्नर और एसडीएम से मुलाकात करेंगे और रेरा के तहत न रजिस्टर्ड प्लॉटों की जानकारी लेकर ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान शमसूल आलम के साथ दुर्ग संभाग अध्यक्ष अनिरुद्ध वर्मा, नमन पटेल, आरिफ अहमद खान, मनोज पटेल, मनोज कुर्रे सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जोगी कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार से अवैध प्लॉटिंग की समस्या पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

ग्राम परसापाली में सात दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर का भव्य समापन

पिथौरा(समय दर्शन)। चंद्रपाल डड़सेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा के प्रभारी प्राचार्य करुणा दुबे के मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम अधिकारी शेखर कानूनगो के कुशल संचालन से ग्राम परसापाली में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर में पुरस्कार वितरण एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के पश्चात शिविर का समापन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत सदस्य पिथौरा शैलेन्द्री लक्ष्मीचंद ध्रुव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य एवं संरक्षक करुणा दुबे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला संगठक एनएसएस महासमुंद डॉ. मालती तिवारी, ग्राम परसापाली के सरपंच तुलाराम ध्रुव, उपसरपंच सोनू राम ध्रुव, सचिव हरिहर यदु, ग्राम प्रमुख रूप सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महाविद्यालय से जितेंद्र पटेल ग्रंथपाल, सहायक प्राध्यापक ईश्वरलाल पटेल एवं टिकेश्वरी ध्रुव तथा राकेश तिवारी, रामकुमार रविदास, डेरहीन ध्रुव, छबिलाल पटेल, योगेश पटेल, इंद्रकुमार ध्रुव, नवीन बढ़ाई, छबिलाल यादव आदि कर्मचारीगण भी समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके पश्चात ग्राम परसापाली की बालिकाओं द्वारा आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्वागत उद्बोधन के उपरांत सरपंच तुलाराम ध्रुव ने अपने संबोधन में महाविद्यालय परिवार एवं आयोजनकर्ताओं को सफल शिविर आयोजन के लिए बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। विशिष्ट अतिथि डॉ. मालती तिवारी ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों, दायित्वों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों से अवगत कराते हुए शिविर में किए गए कार्यों की सराहना की। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य करुणा दुबे ने शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगियों को बधाई दी। मुख्य अतिथि शैलेन्द्री लक्ष्मीचंद ध्रुव ने भी अपने संबोधन में स्वयंसेवकों के उत्साह, अनुशासन एवं सेवा भावना की प्रशंसा की। तत्पश्चात स्वयंसेवकों एवं ग्रामीणों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सात दिवसीय शिविर में प्रेमनारायण सिन्हा सहित 20 से अधिक वरिष्ठ स्वयंसेवकों का सक्रिय सहयोग रहा। दलनायक नूतन कुमार एवं दलनायिका ज्योति बाधवानी के नेतृत्व में राहुल चौधरी, मेघा सिन्हा, तुषार साहू (बरेकैल), तुषार साहू, प्रीति चौहान, एकता मिर्धा, आंशिका प्रधान, देवासिनी यादव, जूही भोई, मोहन नायक, रूपा साहू, छाया साहू, भलेश साहू, प्रशांत सिन्हा, कान्हा निषाद, पुष्पराज पटेल, तुषार महापात्र, चन्द्रशेखर नायक, हिमांशु नायक, अमन पटेल, जिर्मला ठाकुर, संजय पटेल, प्रवीण सिदार, रोहन पटेल, जिनमणी ग्वाल, खेमचंद पटेल, लंकेश्वर, भानुप्रताप नेटी, देव सोनवानी, कुलजीत, टिकेलाल दीवान सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने सहभागिता निभाई। समापन अवसर पर शिविर में उत्कृष्ट सहभागिता के लिए सभी स्वयंसेवकों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों को श्रीफल एवं मोमेंटो भी कार्यक्रम उपरांत प्रदान किया गया। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी शेखर कानूनगो के साथ साथ टिकेश्वरी, रामकुमार रविदास, राकेश तिवारी, डेरहीन ध्रुव, छबिलाल पटेल प्रत्येक दिवस जुड़े रहे। शिविर का समापन आभार प्रदर्शन एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संदेश के साथ किया गया।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26